श्री रोशन लाल मैं लास्ट मे क्लैरिफिकेशन करूगा।

SHRI RANBIR SINGH He does not want any clarification . . .

MR DEPUTY CHAIRMAN You please don't interrupt I know what I am doing here I am asking him If all the Members do like this, then where is the need to have a Chair and where is the need to have a Minister here? Mr Roshan Lal, you please have your say The Minister is there to refute if there is anything wrong

श्री रोशन लाल एक चीज मै और कहना चाहता हू।

MR DEPUTY CHAIRMAN What is the clarification?

SHRI ROSHAN LAL Delay tactics . . .

(*Interruptions*) सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी हाल ही मे राजस्थान सरकार को यह हिदायत की थी कि हर महीने 2000 परिवारो की आबादकारी की जाय लेकिन राजस्थान सरकार वहा पर डिले टैक्टिस लगाती रही और उन्होने इन्कार कर दिया कि हम दो हजार नही ले सकते। उस हिसाब के अनुसार हर तीसरे दिन ढाई सा फैमलीज को वहा जाना था। उन्होंने उनको लेने से इन्कार कर दिया और

MR DEPUTY CHAIRMAN How you take your seat . . .

श्री रोशन लाल अब हम पर डिले टैक्टिस का इल्जाम लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हिमाचल गवर्नमेंट मदाखलत करती है। मै यह बाजे कर देना चाहता हू कि हम 250 फैमलीज हर तीसरे दिन उन के यहा भेजना चाहते थे उसके लिए उन्हाने इन्कार कर दिया। मै मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हू कि जो आज वहा पानी भर रहा है और 70 हजार आदमी जो वहा पानी के नजदीक बैठे हुए है क्या आप उनकी वार फुटिंग पर मदद करेंगे और मिलिटरी को हिदायत करेंगे कि उन की मदद करे इसलिये कि हर आदमी अपने डगर, पशु और अपना सामान अपने साथ ले जाना चाहता है। वहा जाने से कोई इन्कार नही करता, लेकिन क्या आप उन का वहा ले जाने से इन्कार करते है। हम किसी नैशनल इटरेस्ट मे बीच मे नही आना चाहते और हम को पानी देने से भी कोई इन्कार नही है। हम तो फक्त उनका रिहैबिलिटेशन चाहते है। पजाब को, राजस्थान का और हरियाणा का आज हिमाचल का पानी जाता है और जिस की वजह से वहा गदम काफी हो सकता है। तो आप इन बातो का जवाब दे।

DR K L RAO Sir, I am glad on account of the sentiments he has expressed That is a very happy sign I should like to submit this

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR He has alleged something against the Rajasthan Government

DR K L RAO Sir, Iam glad on ac- are not closed, the water will rise up to 1325

SHRI RANBIR SINGH Water will remain on the dam for only 4-5 days?

DR K L RAO Even when the tunnel is not closed, the water will rise to 1325 About 14000 people will be affected I will request the hon Member from Himachal Pradesh and his friends that they use their best efforts to get these people out of this 1325 Water may get there any time in the month of July

MR DEPUTY CHAIRMAN I think, now we come to the Finance Bill Mr Shejwalkar

SHRI RANBIR SINGH There is one thing, Sir

MR DEPUTY CHAIRMAN There is no question of anything now

THE FINANCE BILL, 1973—*contd.*

श्री ना० कृ० शेजवलकर (मध्य प्रदेश) माननीय उप-सभापति महादय, आज सदन के सामने 1973 का यह वित्त विधेयक विचार के लिये है। पच्चीस वर्ष स्वतन्त्रता के आने के बाद हो गये है और उसकी सिलवर जुबली मनाई जा रही है, यह रजत-जयन्ती वर्ष है और इस रजत-जयन्ती के वर्ष मे दुर्भाग्य से चारो तरफ भूख, दगे, बिजली का अभाव है, कीमते बढी हुई है, पानी का अभाव है। यह सारी जो स्थिति है वह आज हम देख

रहे है। वैसे तो देखा जाय तो जब जब भी फरवरी का महीना आता है और २८ फरवरी की तारीख आती है तो सारा देश एक तरह से घबडाहट मे आ जाता है उसको एक घबराहट होती है कि न मालूम कौन से नये नये कर अब लगने वाले है और अब न मालूम क्या क्या मुसीबते आने वाली है और उसके बाद सारा उसका जो परिणाम है वह सारे भारतवर्ष को भुगतना पडता है।

'गरीबी हटाओ' का नारा लगाये हुये दो वर्ष हो गये। कभी कह दिया जाता है कि गरीबी तो मेरी जिन्दगी मे भी नहीं हट सकती और कभी फिर कहा जाता है कि हम तो गरीबी हटाने के लिये बन्धे हुये है। कभी हमारे वित्त मंत्री महोदय उपदेश देते है कि होल्ड दि प्राइस लाइन प्राइस लाइन को पकड कर रखो। मै जब विद्यार्थी था तो ज्योमेट्री मे पढाया जाता था—लाइन हैज नैथर ब्रेड नोर ब्रेथ—इसलिये यही कारण है कि उनको इस लाइन को पकडना ही नहीं आता क्योकि ब्रेथ है ही नहीं तो कहा से पकडे। तो यह स्थिति है कि हर बार कीमते बढती चली जा रही है। बजट जब लाया गया तो एक फैलसी सामने थी उसके पहले पिछले सत्र मे पे कमिशन की रिपोर्ट के बारे मे इसी सदन मे प्रश्न उपस्थित हुआ और यह माग की गई—मैने भी प्रश्न पूछा था कि क्या आप सहानुभूतिपूर्वक यह विचार करेगे कि कुछ अन्तरिम सहायता दी जाय तो उन्होने कहा कि सहानुभूति तो है लेकिन अन्तरिम सहायता हम नहीं देगे। अब उसका कारण स्पष्ट था कि बजट को रखना था उसमे 85 करोड रु० का घाटा प्रस्तुत किया गया और जब रिपोर्ट आयेगी तो उनको पता था कि उससे भी सैकडो करोड रुपये का घाटा होने वाला है और उसके अनुसार फिर दुबारा इनफलेशन के लिये महगाई के लिये बडा भारी प्रश्न उपस्थित होने वाला है।

इधर इन सारी समस्याओ का कारण हमारी प्रधान मंत्री जो विरोधी दल है, उनके ऊपर थापने मे भी कभी चकती नहीं है आये दिन ये भाषण होते है कि इस सारे के लिये उत्तरदायी जो है वह विरोधी दल है, हम जो कुछ योजनाये सामने रखते है उन योजनाओ मे ये किसी प्रकार से हमे सहयोग नहीं देते। मै पूछना चाहता हू कि किसी भी जनतंत्र के अन्दर उत्तरदायित्व पहला प्रमुख रूप से किसका है जो शासक दल हो जो दल इतने बडे बहुमत मे हो सारा उत्तरदायित्व उसी का है। दूसरा अगर कोई सहयोग चाहता है तो आखिर जो विरोधी दल है वे तो बनाये हुए नहीं है। उनका भी अपना अपना महत्व है और अपनी अपनी मान मर्यादा है। आप कोई नीति निर्धारित करते है बनाते है अपने आप और फिर आप दूसरो से कहते है कि उसका पालन करो और वे लोग इस बारे मे अपनी राय भी जाहिर न करे तो आप उनसे कहते है कि ये तो हर चीज मे रुकावट डालना चाहते है। अगर राष्ट्र के बारे मे कोई समस्या है और उस समस्या को वास्तविक रूप मे आज का शासन हल करना चाहता है तो उसको विरोधी दल को बताना चाहिये उनसे अलग से बात करना चाहिये कि उनकी इस बारे मे क्या राय है? हो सकता है कि इस तरह की बातचीत के बाद भी कोई नतीजा पर न पहुचा जाय विरोधियो से राय न मिले एक दूसरे से विचार विमर्श करने के बाद भी कोई नतीजा न निकले तो उसके बाद भी यह कहा जा सकता है कि हम आप का इस बारे मे सहयोग चाहते है। लेकिन एक दिन कोई महानुभाव किसी अधिवेशन मे किसी चीज को अचानक रख देते है और उस चीज के बारे मे जब कि उनके दल मे हो दो राय है उस चीज के बारे मे कहते है कि विरोधी लोग इस चीज को नहीं करने देना चाहते है और हमारे रास्ते मे अडगा लगाना चाहते है। पहले बैंक का राष्ट्रीयकरण करने का प्रश्न आया तो उस समय भी यही कहा गया था कि हम लोग तो प्रगति करना चाहते है, लेकिन विरोधी लोग हमारे मार्ग मे बाधक है हम प्रिवी पर्स समाप्त करना चाहते है मगर ये नहीं करना चाहते है और इस तरह से ये लोग हमारे रास्ते मे रुकावट डालना चाहते है। मै आप से पूछना चाहता हू कि आपने दो काम कर लिये, क्या उसमे आपको रुकावट आई? एक मामले मे कुछ रुकावट आई कि मामला

[श्री ना० कृ० शेजवलकर]

कोर्ट मे गया, लेकिन उसके बाद तो आपका काम हो गया । लेकिन मै यह जानना चाहता हू कि इसका परिणाम क्या निकला? मै यह कहना चाहता हू कि आप हमेशा से यह कहते आ रहे है कि इन चीजो मे गरीबो को लाभ होगा बैंक के राष्ट्रीयकरण करने मे । आज यह स्थिति हो गई है प्राइवेट बैंको से जहा पहले जनता की सेवा होती थी; क्योकि स्टेट बैंक को तो सरकारी काम-काज से ही फुरसत नही मिलती है, लेकिन आज राष्ट्रीयकरण करने के बाद से उन बैंको मे भष्टाचार फैल गया है । पहले मुझे उनके कार्यप्रणाली के के बारे मे बडा गर्व था, लेकिन आज यह स्थिति हो गई है कि उन बैंको के अन्दर भी भ्रष्टाचार घुस गया हे । अगर किसी गरीब काश्तकार को 500 रुपये का कर्जा लेना होता है तो उसके हाथ मे केवल 200 रुपया ही मिलता है । आज जो गरीब लोग है उनको इन बैंको से किसी तरह की भी मदद नही मिल रही है । मै आपके सामने मध्य प्रदेश का उदाहरण देना चाहता हू । वहा पर इजीनियरो को 20 लाख रुपया कर्जा देने की बात थी और यह कर्जा वहा पर तीन लड़को को मिला । इनमे से एक लड़का तो चीफ सेक्रेट्री का था, दूसरा एक भूतपूर्व मुख्य मत्री का था और तीसरा एक बड़े अधिकारी का लड़का था। इस तरह से जो 20 लाख रुपया बेकार इजीनियरो के लिए था, वह इस तरह से तीन लड़को का दे दिया गया ।

श्री महावीर त्यागी (उत्तर प्रदेश): यह कहा की बात है ।

श्री ना० कृ० शेजवलकर यह मध्य प्रदेश मे, भोपाल की बात है । इस तरह का मारुत्ति लिमिटेड का एक बहुत बड़ा किस्सा हो गया है । यह कम्पनी अभी तक रजिस्टर्ड नही हुई और न इसको अभी लाइसेस ही मिला, लेकिन इसको फाइनेन्स कारपोरेशन से लाखों रुपया कर्ज के रूप मे मिल गया है । इस तरह की बात पहिले नही होती थी । कुछ मात्रा मे होती होगी, लेकिन आज तो इस तरह की बात ह आम बात हो गई है ।

अब सरकार ने अनाज का व्यापार अपने हाथ मे ले लिया है । आप अगर यह समझते है कि हम इन व्यापारियो के हमदर्द है तो मै यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हू कि हमे व्यापारियो से कोई बडी हमदर्दी है, इस तरह की जो बात आपके मन मे है उसको आप मन से निकाल दीजिये । लेकिन जो कोई समाज विरोधी तत्व है, उनके साथ हमारी कोई हमदर्दी नहीं है । मै यह शब्द "जो कोई" के ऊपर विशेष बल दे रहा हू, क्योकि हम देखते है कि कुछ सरकारी अधिकारीगण भी इस कार्य मे लगे हुए है तथा कुछ अन्य लोग भी है जो इस तरह के कार्यो मे मिले हुए होते है । इस तरह के लोगो के लिए आपने कोई योजना और कोई उपाय नही किया । इसी बात पर हमारी आपत्ति है, क्योकि हम देखते है है कि मध्य प्रदेश से जो इन्स्पेक्टर गेहू खरीदने हरियाणा गये थे, उन्होने एक रुपया बोरी वसूल किया । भाव कुछ भी हो, 74,76 या 82, यह उनके ऊपर निर्भर होता है । क्या आप इन्ही के आधार पर योजनाओ को सफल बनाने की बात सोचते है ?

बड़ी खुशी की बात है कि आपने इन्कम टैक्स एक्ट मे एक प्रावधान कर दिया कि कोई कम दर पर अपनी सम्पत्ति को बेचेगा तो सरकार का उसको लेने का अधिकार हो सकता है । मैं एक दूसरी बात रखना चाहूगा—मैंने पिछले वर्ष भी वित्त मत्री महोदय से सवाल किया था और आज भी जानना चाहूगा—कि अगर कोई अधिकारी जानबूझकर कीमत ज्यादा लगा कर एसेसमेंट करने की कोशिश करे तो ऐसे भी यह कह सके कि सरकार यह कीमत निर्धारित करती है तो सरकार इस कीमत मे ले ले, आप्शन उसका भी हो । यह सब मिली भगत है । आपका टैक्सेशन का जो स्ट्रक्चर है वह बहुत कम्प्लीकेटेड है, उसमें बहुत लूपहोल्स है । इसके कारण दोनो मिल कर जनता के धन को लूटते है । आज आपने चाहे राजा खत्म कर दिए होंगे, लेकिन आज दूसरे राजा बन रहे है । आज एक साधारण मोटर वैहिकिल्स का टैक्स इस्पेक्टर कार रख सकता है, जिसकी 250—300 तनख्वाह होती है । पुलिस का इस्पेक्टर, जिसकी 250—300 तनख्वाह होती है, 200 रुपये महीना मकान का किराया दे सकता है, 100 रुपए की ट्यूशन रख सकता है और 500 रुपये के उसके अपने निजी नियमित खर्चे है, यह सब वता सकते है । आज

चम्बल का पुल टूट गया, फला जगह का पुल टूट गया, इनक्वायरी बैठ गई। पी० डब्ल्यू० डी० मे क्या है ? हर विभाग मे यही हाल है। फारेन एक्सचेंज बिल पर चर्चा का मौका मिला था। लाखो रुपये की स्मगलिग होती है। अगर हम और आप जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति होते है तो उनके लिए बराबर कानून का पालन होगा, अगर आप एक शर्ट का कपड़ा भी ले आये तो पैनल्टी देनी पड़ेगी, लेकिन मै देखता हू कि हजारो घडिया, हजारो ट्राजिस्टर, हजारो टेलीविजन, मोटरे भी, रेफ्रीजैरेटर सब यहा आ जाते है। क्या ये सब यो ही पास हो जाते है ? जो स्मगलिग करते है और जो उनके साथ मिले होते है, उन दोनो की साठ-गाठ होती है। इसको प्रश्रय देने वाले है राजनीतिज्ञ, जो अपने दल के हित के लिए या अपनी सत्ता को बनाये रखने के लिए ऐसे तत्वो को प्रश्रय देते है। आपने इस समस्या के मूल्य को देखने का प्रयास नही किया। मै चेलेंज देकर पूछना चाहता हू --आप जनसघ को बराबर दोष देते है --आप बताइए कि कितने बडे व्यापारी है अनाज के जो हमारे साथ लगे है। एक-दो प्रतिशत होगे। आप देखेगे सारे खादी--वेशधारी शासन के पीछे, अधिकारियो के पीछे घूमने वाले लोग नजर आएगे। हमको उनके साथ हमदर्दी नही हो सकती। हमको हमदर्दी किसाना से है, जनता से है। इस सबका परिणाम यह होता है कि ये भ्रष्ट अधिकारी किसान को सही कीमत मिलने नही देते। हमे व्यापारी से कतई हमदर्दी नही है। आप उनको रोकेंगे जो एक-दो रुपया मुनाफा कमाते है और आपके एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज 20 और 24 रुपए क्विन्टल पड़ते है, फूड कारपोरेशन देता है। फूड कारपोरेशन की हालत आपको पता है। हजारो टन गल्ला सड गया, लाखो रुपयो का नुकसान हुआ। उसके चेयरमैन, एफ० सी० आई० के चेयरमैन के खिलाफ क्या-क्या हुआ, आप सब जानते है।

आपका टैक्सेशन का स्ट्रक्चर ही खराब नही है, पब्लिक अडरटेकिंग्स मे भी घाटा होता है। उसका भी कारण यही है। अब कोई आदर्श उपस्थित करने के लिए तैयार नही है। केवल कागजो मे या भाषण देने से आदर्श उपस्थित नही होगा, व्यक्तिगत आदर्श उपस्थित करना पड़ेगा। आप मुझे क्षमा करेगे, मैं व्यक्ति को डिस्कस नही करना चाहता, लेकिन अगर प्रधान मत्री जी यह तर्क दे कि मैं अपने लड़के के लिए मोटर का कारखाना क्यो नही खोल सकती, उसने क्या गलती की है तो वह तर्क हर एक के लिए उपलब्ध होगा।

आज भारत के लिए त्याग की आवश्यकता है। अगर वह इस चीज को सामने रखते। इस प्रकार का आदर्श उपस्थित करते तो शायद दूसरे लोग भी उसकी मांग न करते तो आज देश के सामने दूसरा ही चित्र होता। मै अपने बारे में भी कहता हू कि अगर आज लोग आदर्श उपस्थित करे तो देश का उदाहरण ही दूसरा होता। लेकिन हम लोग बाते करते है पर उसके मूल को हम देखना नही चाहते। ऊपर-ऊपर मरहम पट्टी वाले हल निकालते जाते है, इसलिए हम दिन प्रति दिन नीचे चले जा रहे है।

ग्रोथ रेट हमारा कम हो गया। 900 करोड रुपये के लगभग हमारा उत्पादन इस वर्ष कम हो गया। बिजली की बहुत बड़ी कमी है। पावर शार्टेज की वजह से यह परिस्थिति उत्पन्न हुई। क्यों नही हम उसके बारे मे एक ऐसी योजना बनाते कि जिसमें सारे समाज का एक-एक व्यक्ति सम्मिलित होकर उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेकर तैयार होता ? सारी चीज नारेबाजी से तैयार की जाती है। मुझे याद है कि सन् 1957 मे अमरीकन कपनी की तरफ से कहा गया कि हम फर्टिलाइजर कपनी खोलने के लिए तैयार हैं। लेकिन उस समय यह बात कही गयी कि 51 प्रतिशत शेयर भारत सरकार के होगे। लेकिन उस कपनी ने सोचा कि इसमे रोज-रोज का इंटरफियरेंस होगा, हस्तक्षेप होगा और वह तैयार नही हुई। आज दुर्भाग्य यह है कि सर्व-साधारण और अधिकारियो के बारे मे यह विश्वास नही है कि कोई ईमानदारी से या नेकनियती से काम करेगा। अगर हमारे पंडित जी इस बात पर न अड़े होते तो शायद उस समय फर्टिलाइजर्स आ गया होता और जो सूखे की स्थिति आज है वह न होती और हमारी योजना सफल होती।

कहा जाता है कि इन दिनो मे हमने प्रगति की है और हमको फारेन टेकनीक की आवश्यकता

[श्री ना० कृ० शेजवलकर]

नहीं है। लेकिन मैं देखता हूं कि व्यावहारिक रूप में छोटी से छोटी मशीन क्या न हो हम नहीं बना सकते। आज युग कितना आगे चला रहा है दुनिया की दौड़ में हम कितने पीछे हैं और फिर भी हम यह नहीं चाहते कि कोई दूसरा हमारे यहां आये। यह मैं मानता हूं कि बैलेंस हमें देखना पड़ेगा कि हमारा फारेन ऐक्सचेंज व्यर्थ न जाये, लेकिन इतनी सख्ती रखने से नतीजा यह होता है कि आपका उत्पादन कम हो रहा है। अगर आप ऐसी योजना बनायें कि उत्पादन ज्यादा हो और जितना फारेन एक्सचेंज बाहर भेजेंगे उससे ज्यादा कमाकर देंगे इन टर्म्स पर कोला-बोरेशन करें तो बहुत ज्यादा सुधार हो सकता है, इससे क्वालिटी देश में सुधर सकती है और देश में बड़ा भारी परिवर्तन आ सकता है। बहुत से देश हैं जिन्होंने यह बात तय की कि हम दूसरों का ज्ञान देंगे। हमारे देश का एक एक व्यक्ति इतना बुद्धिमान है कि उसको देखने की जरूरत है वह उसकी नकल कर सकता है। रिपेयर में हर बात में वह बुद्धिमान है उसको देखने का मौका तो मिले काम करने का अवसर तो मिले। इसके बारे में एक ऐसी पालिसी आपकी है जिसके कारण आज हम औद्योगिक क्षेत्र में विकास नहीं कर पा रहे हैं।

अनएम्प्लायड लोगों का प्रतिशत पढ़े-लिखे अनएम्प्लायड लोगों का प्रतिशत 43 परसेंट बढ़ गया है। अब आप सोचिये कि 43 परसेंट बढ़ गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे गलत न समझें, मैं मोनापोलिटी के पक्ष में नहीं हूं लेकिन मैं यह कहता हूं कि एम्प्लायमेंट का अगर आप हिसाब लगायेंगे तो जब से आपने पब्लिक अंडर-टेकिंग्ज हाथ में ली हैं एम्प्लायमेंट पोटेंशल कम हो गया है। उसका कारण यह है कि उसमें आप लाभ नहीं कमा रहे हैं, विकास नहीं करते। प्राइवेट इन्डस्ट्रियलिस्ट्स स्टाफ और दूसरों को ज्यादा पैसा देते हैं और हर साल नया कारखाना लगाते थे। उससे इम्प्लायमेंट पोटेंशल बढ़ता था। लेकिन आपकी पालिसी के कारण अनएम्प्लायमेंट का परसेंटेज बढ़ गया। इतने ज्यादा आज अनएम्प्लायड हो गये इंजीनियर्स कि वे आज बैंकों में नौकरी करते हैं रोज ए क्लर्क। ऐसे उदाहरण मेरे पास हैं। तो यह स्थिति आज देश के अन्दर है और इस तरह की निराशा की स्थिति बनी हुई है। इसका कारण यह है कि इस अनएम्प्लायमेंट के बारे में दुर्भाग्य से आज इस सरकार का कोई दृष्टिकोण है नहीं जिसके कारण से आगे कोई हल नजर नहीं आता।

इसी प्रकार से आपने बिजली के उत्पादन का काम किया। मुझे याद है कि पिछली बार जब बिहार में सूखा पड़ा था तो उस वक्त वहां संविद सरकार थी। उनमें चाहे जो भी दोष हों लेकिन मैं समझता हूं कि उस समय बिहार की सरकार ने जितना काम किया वह अनुकरणीय उदाहरण है। उन्होंने जगह-जगह पम्प लगाये जगह-जगह उन्होंने पानी के लिए छोटा-छोटा प्रबंध किया।

जिन स्थानों पर हम पानी के लिए आसमान की तरफ देखते हैं महाराष्ट्र में मैसूर के कुछ क्षेत्रों में वहां दो तीन रुपये मजदूरी में काम तो आपने करवाया लेकिन उससे काम चलते हैं नहीं। वहां पर आप छोटे सिंचाई के साधन बनाते तो उसके कारण आप उसी के आधार पर आगे के लिए कम से कम इस समस्या का हल करने में सहायता दे सकते थे लेकिन उसके बारे में कोई विचार नहीं किया गया।

गरीबी का नारा दिया जाता है लेकिन आज 75 प्रतिशत ऐसे गांव हैं जिनके अन्दर न बिजली पहुंची है और न पीने के पानी का प्रबंध है। आपके आवास मंत्रालय ने एक योजना बना दी कि इतने गांव हम प्रत्येक वर्ष लेंगे, लेकिन फिर भी 50 साल में सब पूरे नहीं किये जा सकते। आप प्रमुखता किस चीज को देने वाले हैं। पीने के पानी को आप देंगे नहीं। आप पम्प्स वगैरह को प्रमुखता देंगे नहीं, आप उनके निवास लिये कोई योजना बनायेंगे नहीं, आप तो 26-26 मंजिल वाले भवन बनायेंगे और उनके लिए आप योजना बनायेंगे। आप ऐसी कोई योजना आरम्भ नहीं कर सकते, जिसमें जनता का कोआपरेशन मिले

आप कालोनीज स्वय बनाते है । मै पूछना चहता हू कि आप डोनेशन दे कर क्यो नही स्वयं उनसे उनको कराते है । आप उनको सबसीडी दीजिये । इससे मकानो की संख्या भी ज्यादा बढ़ेगी और सरकार का इंवेस्टमेंट भी कम होगा । यह मानना पड़ेगा कि अब रूस मे भी इस बात पर लोग वापस आने लगे है कि व्यक्तिगत जब तक किसी मे भावना नही होती इंसेटिव नहीं होता, तब तक काम मे उसकी रुचि नही होती है । सरकार के मकान मे लोग उसकी मरम्मत करने को तैयार नही होते है । अगर उसका किराया सौ रुपये होगा तो लोग चाहेगे कि 50 रुपया ही देना पड़े । इसलिए अगर आप उसके ह्यूमन करेक्टर को कंसीडर कर के कोई आवास की योजना बनाये तो यह हो सकता है कि एक बड़ी भारी क्रांति आ जाय । अगर लोग स्वय अपना मकान बनायेगे तो उससे सरकार के ऊपर ज्यादा भार नही पड़ेगा । आप ह्यूमेन एप्रोच को एक तरफ रख देना चाहते है और केवल एक कागजी योजना बना कर चाहते है कि वह कार्यान्वित हो जाय और यही कारण है कि उसमे आपको असफलता मिल रही है । समाजवाद का हम नारा लगाते है, लेकिन समाजवाद वास्तव मे क्या है इसके बारे मे भिन्न-भिन्न रायें है। एक ही दल के अलग-अलग लोग अलग-अलग उस की व्याख्या करते है। अगर उसका अर्थ यह है कि हम विषमता को दूर करे तो हम उसमें साथ है। हम खुद विषमता नही चाहते है । हम नहीं चाहते है कि किसी को दो सौ रुपये तनख्वाह मिले और किसी को 5,000 रुपया मिले । हम ने कहा है कि एक और दस के बीच मे उसका प्रमाण होना चाहिए, आय का और उसको आप करिये ।

आपने और तमाम दूसरे कानून बनाये लेकिन उसमें इस की कोई रोक नही की कि डिस्पैरिटीज को कैसे खत्म किया जाय । इसके लिए आप ने कोई योजना नही बनायी । अगर किसी को दस करोड की आमदनी हो जाय और वह बडी-बडी कोठियों में रहे तो उस पर आप किसी किस्म की रोक नही लगाना चाहते, आप उस पर कोई रोक लगा नही सकते । आज हम लोग स्वयं कोई आदर्श उपस्थित नही कर रहे है । हम लोग चाहते हैं कि हम तो ढाई लाख की कार मे घूमते फिरे और अपेक्षा करते है एक व्यापारी से कि वह किसी विदेशी कार का इस्तेमाल न करे । मै समझता हू कि इस बात का कोई वजन नही होगा । मैं यह बात समझ सकता हू कि जो हमारे केन्द्र के मंत्री है, उन के जीवन का बहुत अधिक महत्त्व है । अगर कोई ऐसी नौबत आ जाय और आप का हिल्स आदि मे दौरा करना हो तो आप उसके लिए कोई विदेशी या और अच्छी कार ले जाय, लेकिन अगर आप को दिल्ली मे ही घूमना है तो फियेट या एम्बेसेडर मे आप क्यो नही घूम सकते ? लेकिन आज ऐसी भावना हमारे मन्त्रियों में नही है । आज ही मुझे पता लगा कि हमारे एक नये मंत्री है, जिन्होने एक नयी विदेशी कार लेने से इन्कार कर दिया और अपने पुराने फ्लैट मे ही रहना पसंद किया है । यह एक अच्छा उदाहरण है । अगर सभी लोग ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करे तो एक अच्छा वातावरण तैयार हो सकता है । कोई एक नया कानून बनाने से कोई विशेष परिवर्तन नही आ सकता हम गलती करे और दोष विरोधियो पर मढ़ दे यह ठीक नही है । आज कहा जाता है कि विरोधी हमारे दल को सैलाइन करने की कोशिश कर रहे है, लेकिन आप चुनाव किस तरह से जीते है । यह चुनाव विरोधियो को सेलाइन कर के ही तो जीता गया है । मेरा तो आरोप है कि विरोधियो को सेलाइन करके तो वह लोग यहा आये है । हम कहते है कि हम साम्प्रदायिक नही है । हमारे सगठन मे अनवर देहलवी है, हमारे यहा अब्दुल रहमान है, कानपुर मे एक मुसलमान हमारे मेम्बर है, लेकिन उस सब बात को वह नही मानेगे । इसके बाद भी वे नही मानेगे कि हम लोग साम्प्रदायिक नही है । समझते हुए भी वे कहते रहेगे कि हम लोग साम्प्रदायिक है । व्यापारियो से वे चन्दा खुद ही इकट्ठा करते रहेगे और आरोप हम पर लगायेगे कि हम उन से पैसा ले रहे है और हम व्यापारियो से मिले हुए है । आपके यहा साठ,-साठ लाख रुपये की रकम का कोई पता नही चलता, उस के बारे मे आज तक कोई सही स्टेटमेट नही दिया जा

[श्री ना० कृ० शेजवकर]

सवा और आरोप हम पर लगाया जा रहा है। समाजवाद का नारा लगाते है और एक प्राइवेट कम्पनी खुद ही घर मे चला दी जाय तो उस मे दोष किसका है? इसमे हमारी पार्टी का कोई दोष है या आप का? मेलाइन आप कर रहे है या हम कर रहे है? तो आप देखे कि वास्तविक स्थिति आज क्या है। टैक्सेशन ला आप ने इतना कॉम्प्लिकेटिग बनाया हुआ है, उसमे इतने डिडक्शन्स होते है और इतने झगडे करने पडते है कि उसके कारण वह सिम्पुल नही रहा है जब कि कानून साधारण व्यक्ति की समझ मे भी आना चाहिए। मै भी 27 साल की स्टैंडिंग का वकील हू, लेकिन मुझे भी तीन-तीन बार कुछ बातो को देखना पडता है और इन्कम टैक्स के रेगुलर प्रेक्टीशनर्स से पूछना पडता है। मै तो कोई पापुलर मत्री नही हू कि दस साल तक रिटर्न दाखिल न करने पर भी कह दू कि रिटर्न दाखिल करना भूल गया, मुझे याद नही रहा। तो ला को सिम्प्लीफाई करने का प्रयत्न होना चाहिए

वित्त मंत्रालय मे उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मै एक स्पष्टीकरण चाहती हू। मै कोई अनुभवी वकील तो नही हू 27 वर्ष की प्रैक्टिस की, लेकिन आपने कहा कि हम विरोधियो को मेलाइन कर के ही इस चुनाव मे जीत कर आ सके है। तो क्या आप ऐसा कह कर जनता की समझदारी को चुनौती नही दे रहे है? जनता ने जिन को चुन कर भेजा है, उस जनता को आप चुनौती नही दे रहे है, उसकी समझदारी को।

श्री ना० कृ० शेजवलकर : मै ऐसा नही कहना चाहता। जनता के ऊपर हमारी अपार श्रद्धा है, लेकिन जनता तो ऐसे भोलेशकर है। उस को समझ का सवाल ही नही है। भोलेशकर जिस प्रकार होते है उसी प्रकार जनता को जिसने डमरु बजा कर रिझा लिया वह उस की बात मान जाती है. .

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी (मध्य प्रदेश) : आप तो ताडव भी करते है तो भी कुछ नही होता।

श्री ना० कृ० शेजवलकर : तो मेरा निवेदन यह है कि जो कुछ मैने यहा सक्षेप मे निवेदन किया है, उस पर आप गौर करे और शान्तिपूर्वक विचार करे और मै समझता हू कि आप अपने मूलभूत विचारो मे कुछ परिवर्तन करे तो शायद हम कुछ आगे बढ सकते है। मै आपको आश्वासन देना चाहता हू कि आप के किसी नेक कदम मे हम आप के साथ है और हम उसके लिए हर प्रकार से सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं, आप कोई सेक्रीफाइस बाद मे करे, हम पहले करेगे। आप निर्धारित कर दीजिए कि सब एम०पीज० को हम दो सौ रुपये महीना तनख्वाह देगे, मै सबसे पहला आदमी होऊगा और मै कहूगा कि मुझे आप आधी तनख्वाह ही दीजिए। लेकिन आप आदर्श उपस्थित करे, हम आपके साथ आने को तैयार है।

श्रीमती सीता देवी (पजाब) माननीय उपसभापति जी, इस वर्ष इस बजट को सतुलित बनाना और आर्थिक व्यवस्था के मुताबिक बनाना काफी कठिन काम था, क्योंकि सन् 1971 ई० मे देश ऐसी परिस्थितियो मे से गुजरा, बगला देश का प्राबलम था और कई जगह पर अकाल पडा। मै समझती हू कि इन हालात मे जिस किस्म का बजट हमारे वित्त मत्री साहब ने बनाया और कोशिश की कि गरीबो के ऊपर कम से कम भार पडे इसके लिये वह बधाई के पात्र है। फिर भी मै यह कहना चाहती हू कि कितने नेक कदम उन्होने उठाने की कोशिश की और दिल से कोशिश की, लेकिन हमे एक खदशा यह है कि जो नेक कदम उन्होने उठाया और उठाने की कोशिश की उसके बावजूद ऐसा न हो और जैसा कि हम देखते है कि जिस किस्म से हमारे काम चलते है, उससे वह लाभ नही हो पाता जो कि होना चाहिये। जैसे कि बैंको का राष्ट्रीयकरण किया गया। उसका पहला अभिप्राय यही था कि जो गरीब लोग है, किसान मजदूर है, गरीब जनता है, उनको किसी प्रकार से लाभ हो, उनको कोई लोन मिले, वह कोई छोटा-मोटा व्यापार कर सके, कोई रिक्शा वाला रिक्शा बना ले, कोई स्कूटर वाला स्कूटर बना ले, कोई टैक्सी बना ले और वह अपना व्यापार करे। मेरा अपना अनुभव है क्योंकि मै गरीब लोगो के अन्दर, मजदूरो मे,

काम करती हू, कि उसका वह लाभ उन लोगो को नही मिल रहा है। ऐसा लम्बा चौडा प्रोसीजर है कि उन प्रोसीजरो म से जो गरीब आदमी है उसका निकलना बडा मुश्किल हो जाता है--यह सिक्योरिटी लाओ, वह सिक्योरिटी लाओ और फिर बीच मे जैसा कि हमारा कैरेक्टर है कुछ रुपया भी लेते है। तो मै मिनिस्टर साहब का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहती हू कि उन प्रोसीजरो को जैसे भी हो कुछ सिम्प्लीफाई करने की कोशिश करे। 14 करोड रुपये के डाइरेक्ट टैक्सेज लगाये गये है और बाकी इनडाइरेक्ट टैक्सेज लगाये गये है। ठीक है, टैक्सेज लगाना बडा जरूरी है, जिस देश ने आगे बढना है, आगे प्रगति करनी है, फाइव ईयर प्लान्स को पूरा करना है, तो टैक्सेज तो लगाना ही है, बिना टैक्सेज के तो काम नही चलता लेकिन टैक्सेज वह लगाना चाहिये जिनका कि जो गरीब है जो मध्यम वर्ग है उसके ऊपर बहुत कम असर पडे। मै बहुत वर्णन नही करना चाहती, लेकिन पैट्रोल के ऊपर उन्होने कहा कि हमने 8 पैसा लगाया है, देखने मे तो 8 पैसा बडा कम लगता है, लेकिन उसका प्रभाव क्या पडा है? आप देखिये कि स्कूटर है, टैक्सी है, कारे है, उनमे किराया बढ गया। क्यो किराया बढ गया? वह सीधे कहते है कि आपकी सरकार ने पैट्रोल महगा कर दिया। इसका जो मध्यम वर्ग है, जो लोअर मिडिल क्लास है, उनके ऊपर बहुत प्रभाव पडा है। इसी प्रकार से जो स्टेनलैस स्टील है और जो छोटी-छोटी चीजे है जिनकी आवश्यकता पारिवारिक रूप से एक मध्यम वर्ग के परिवार को है, उसका बहुत ज्यादा बोझा उनके ऊपर पडा है और उनको बजट सतुलित करना मुश्किल हो गया है।

तो मैं यह कहना चाहती हू कि बडा अच्छा होता कि आप शराब के ऊपर दुगुना टैक्स लगा देते, अगर वह यह करते तो मैं बडा मुबारकबाद देती मिनिस्टर साहब को। यह शराब जिसकी कि पंजाब के अन्दर एक एक फर्लांग पर दुकाने खुली हुई है जिसके पीने से हमारा मारल इतना गिर रहा है, उस शराब के ऊपर अगर ज्यादा टैक्स लगा देते तो इससे रेवेन्यू भी हो जाती और शायद गरीब आदमी को उसके कुछ कम पीने से बचत भी हो जाती। पता नही उन्होने क्यो नही इस तरफ ध्यान दिया और क्यो यह उचित नही समझा।

श्री गनेशी लाल चौधरी (उत्तर प्रदेश) आपकी गवर्नमेंट को हानि होती इसमे।

श्रीमती सीता देवी: चलिये, वह तो ऐसा ही है, गवर्नमेंट तो चलानी ही होती है। दूसरी एक और चीज है जिसकी तरफ मैं उनका ध्यान दिलाना चाहती हू, वह यह है कि हम जिस समाजवाद को लाना चाहते है और हम जो चाहते है कि गरीब और किसान और मजदूर और अमीर मे अन्तर खत्म हो जाय, कम हो जाये एक और
4 P.M. दम का हो जाए। वह कैसे हो सकता है? जब तक हम उसके लिए कोई बहुत बडा कदम नही उठाएगे और मैं यह समझती हू, जब तक हमारे देश के अंदर से ब्लैक मनी खत्म नही होगा, तब तक देश मे समाजवाद कभी नही आएगा चाहे हम उसके लिए कितनी भी कोशिश करे। उसके लिए बहुत बडे प्रयत्न करने पडेगे। मै मिनिस्टर साहब से कहूगी कि उसके लिए आपको बडा स्ट्राग मेजर्स लेने पडेगे, इस ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए। मेरे दिल मे एक सुझाव है, जैसा लका के अंदर किया गया था कि एक ही रात मे आर्डर किया गया था कि जो 100 रु० के नोट है व बाहर निकल आए, वे आगे नही चलेगे। जो लोग इन नोटो को दबा कर रखे है आखिर किसी शक्ल मे--100 रु० के 500 रु० के या 1,000 रु० के--रखे होगे और अगर हमारी गवर्नमेंट मुनासिब समझे इस किस्म का डिक्लेयर कर दे कि वे आगे नही चलेगे। लेकिन यह न हो जैसा कि अब की हुआ कि जमीनो की सीलिग होनी है कहा, तो लोगो ने जमीन अपनी-अपनी सम्भाल ली, इसके नाम कर लिया उसके नाम कर लिया ताकि कोई जमीन बचे नही। मुझे तो पंजाब का अनुभव है, जो बडे-बडे लोग है, जो बहुत बडे जमीदार थे, उन्होने क्या किया कि अपने जो उसके मुजारे थे--इसके नाम 400 एकड, उसके नाम 400 एकड रख कर जमीन की सीमा को खत्म कर दिया और उनसे प्रो-नोट लिखवा कर रख दिया। अब उस गरीब के नाम न 20,000 रु० होगा, न वह

[श्रीमती सीता देवी]

जमीन का मालिक बनेगा। जमीन का मालिक वह जमींदार खुद का खुद ही रहा। यह जो मै आपको बता रही हू यह बिलकुल एक फैक्ट है, जो कुछ वहा हुआ है और सूबो मे भी हुआ है। मैने पजाब का वाकया आपके सामने बताया। तो अगर बात पहले निकल जाए गवर्नमेंट से तो जो पूजीपति है, जो एपार्चुनिस्ट लोग है वे सावधान हो जाते है। मेरा तो विश्वास है कि यह बडी भारी लडाई हमे लडनी पडेगी इस सरमायादारी के खिलाफ, अगर हमे सचमुच मे समाजवाद लाना है। जैसा आपने देखा जजेज के केस मे तूफान मचा हुआ है, नीचे की दुनिया ऊपर आ गई है। क्यो आ गई है? आफटर आल, अगर हमने उन नीतियो का इम्पलीमेंट करना है जो समाजवाद की नीतिया है, तो उसके लिए हमे सुधार करने पडेगे, उसके लिए अपना रेडिकल स्टेप आगे बढाएगे। तो यह एक बहुत बडा रेडिकल स्टप उठाया गया है, जिसके लिए तूफान मचा है। इसी तरह मे मै कहना चाहती हू ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए एक बडा भारी रेडिकल स्टेप उठाना पडेगा। मेरा एक सजेशन था--मिनिस्टर साहब इसके बारे मे ज्यादा सोच सकते है--एक और चीज है जो कि हमे करप्ट करती है और वह यह कि चाहे एम० एल० एज़० हो, चाहे एम० पीज० हो, आए दिन वे पार्टी बदलते है--सवेरे एक पार्टी मे है, दोपहर को दूसरी पार्टी मे है और शाम को तीसरी पार्टी मे है। किसी ने 20 हजार रु० दे दिया, दूसरे ने 30 हजार रु० दे दिया, तीसरे ने 40 हजार रु० दे दिया। यह चीज जहा करप्ट करती है वहा उनके कैरेक्टर को भी गिराती है और ब्लैक मनी बढता है, साथ ही ब्लैक मनी वालो की हिम्मत बढती है। तो कोई ईमानदार आदमी 20,000 रु० किसी को यू ही नही दे सकता, वही देगा जिसके पास ब्लैक का रुपया है। वह सोचता है कि मेरी पार्टी वाले आदमी की हुकूमत होगी तो वह हमे और ज्यादा फायदा पहुचाएगा। अगर 10 लाख रु० एक ब्लेक मार्केटियर उसके लिए इकट्ठा करता है तो उसको 10 करोड रु० कमाने की आशा रहती है। वह इसमे प्राफिट की आशा रखता है। तो मे सोचती हू, जब तक यह ब्लैक मनी हम खत्म नही करेगे, तब तक हमारा समाजवाद नही आ सकता।

एक और सजेशन है। महगाई बेहद बढ रही है इसलिए जो आर्गेनाइज्ड लेबर, है, आर्गेनाइज्ड यूनियन है, वह आए दिन आदोलन करती है, आदोलन करके उनकी तनख्वाहें बढ जाती है। ठीक भी है बढनी भी चाहिए, महगाई जो है, पर उनकी तनख्वाहे बढने से कुछ नही होगा, क्योकि महगाई दुगुनी बढ जाती है। इसलिए मेरा सजेशन है मिनिस्टर साहब से कि कीमते जो है, खास तौर से जो खाने पीने की चीजे है, जिन्हे गरीब और मिड्ल क्लास ने खाना है, जैसे चावल है, तेल है, वनस्पति घी है, और रोजाना इस्तेमाल के लिए साबुन है तेल है, मोटा कपडा है इनकी कीमते फ्रीज कर दी जाए। जब तक आप कीमत फ्रीज नही करेगे, चाहे आप कितनी ही तनख्वाह बढाते चले जाए, सरकारी नौकर भी सतुष्ट नही होगे, जो मजदूर वर्ग है वह भी सतुष्ट नही होगा।

मै तो इस हक मे हू कि कीमतो को फ्रीज कर दिया जाय और इसके साथ ही लोगो को सस्ते भाव पर चीज बेची जाय, फिक्स्ड प्राइस पर बेची जाय, सस्ते भाव पर बेची जाय। अगर हम इस तरह का प्रबन्ध कर सकते है, तब ही हम इस चीज का इलाज कर सकते है।

आपने बेरोजगारी की समस्या के लिए पाच करोड रुपया रखा है। मै मिनिस्टर साहब का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहती है कि इस रकम को सही मशीनरी द्वारा खर्च किया जाना चाहिये ताकि जिस चीज के लिए खर्च किया गया है, उससे लोगो को लाभ मिले। अगर उचित चीज पर यह रुपया खर्च नही होगा तो इससे कोई लाभ होने वाला नही है और अगर इस तरह से इसका लाभ दूसरे लोगो को हो जायगा। अगर आपको बेरोजगारी की समस्या को दूर करना है, तो ऐसी बात न हो कि जिनको जरूरत है उनको तो इसका लाभ मिले और जिनको जरूरत नही उनको इसका लाभ मिल जाय। आज हमारे देश मे बेरोजगारी की एक बडी समस्या है। मेरे

पास कुछ आंकडे है जो मै आपके सामने रखना चाहती हू। मैट्रिक की जो फिगर है वह करीब 1,735 लाख के है, अडर ग्रेजुएट की सख्या 9 32 लाख, है ग्रेजुएट की सख्या 6 2 लाख है और अनुसूचित जातियो की 6 7 लाख है। इस कदर जो हालत है बेरोजगारी की तो यह हमारे गवर्नमेट की जिम्मेदारी है कि वह इस बारे म और भी बात सोचे और साधन निकाले, ज्यादा चीजो पर जोर दे ताकि यह जो समस्या हमारे सामने भयकर रूप मे खडी हुई है उसका इलाज हो सके।

एक और बात मे यह कहना चाहती हू कि हम अपने देश म समाजवाद को कभी भी नही ला सकते है, जब तक न्युरोक्रैसी जो अग्रेज हम को दे गये है जब तक यह न्युरोक्रैसी किसी भी प्लान का चलन नही देगी। कभी ऐसा हो सकता है कि समाजवादी प्रोग्राम हो और चलाने वाले लोग न्युरोक्रेसी के हो जिनका समाजवाद पर विश्वास न हो, तो फिर किसी तरह से देश मे समाजवाद आ सकता है। मै यह बात कह कर किसी के ऊपर आक्षेप करना नही चाहती हू। मेरा तो अपना चालीस साल का अनुभव है कि सरकार कोई भी प्रोग्राम तब तक इम्पलीमेट नही कर सकती जब तब वह काम ब्यूरोक्रैसी के हाथ म रहेगा। तो मै यह कहना चाहती हू कि जहा आप बडी बडी चीजो को ठीक कर रहे है वहा पर ब्यूरोक्रैसी का भी ठीक करने की जरूरत है। आप प्रमाशन बेशक आफिसरो का करे लकिन उन लोगो का करे जिनका समाजवाद के ऊपर और इसके सिद्धात पर विश्वास हो। यह नही कि प्रमोशन सीनियरिटी के हिसाब से हो गया और उन्ही आफिसरो को आई० सी० एस० आफिसरो को कर दिया जो हमारे कामो म रुकावट डालते है। अब उन्हे अपना तरीका और रवैया बदलना होगा। लेकिन जब तक इस तरह की चीज का शासन नही बदलती है तब तक यह चीज नही होता है।

हमने बहुत से कार्यक्रम निश्चित किये है। हमने शहरो मे जो सम्पत्ति है उसके ऊपर सीलिग लगाने के बारे मे बात कही है यह बात ठीक है कि बहुत से स्टेटो मे यह बात हो गई है कुछ मे कामयाबी हुई और कुछ मे नही हुई। तो मेरा यह सुझाव है कि यह जो शहरी सम्पत्ति के बारे मे सीलिग लगाने की बात है, यह उतनी ही लगाई जानी चाहिये जितनी आपने गाव की जमीन पर लगाई है। उस गाव की जमीन से जितनी आमदनी होने वाली है यानी जितनी उसकी कीमत है, उतनी कीमत पर शहर म सम्पत्ति होनी चाहिये। अगर आपने इस तरह की बात की तो समानता बनी रहेगी और भेदभाव नही रहेगा। जो किसान है वह यह समझेगा कि हमारे साथ पक्षपात करते है, अगर शहर और गाव की जमीन म आपने सीलिग मे भेदभाव किया।

एक बात म और कहना चाहती हू जो इस हाउस मे और उस हाउस मे रोज उठता है और वह चीनी का मामला है। हमने लोगो से वायदे किये है कि हम उनकी भलाई के लिए बहुत से कार्य करेगे और उनमे चीनी मिलो के राष्ट्रीयकरण की भी बात है। म अपनी सरकार से कहना चाहती हू कि जहा वह बडी बडी समस्याओ का हल कर रही है, वहा पर वह चीनी मिलो का भी राष्ट्रीयकरण कर दे। आज सारे देश म जो हाहाकार चीनी के सम्बन्ध मे उठ रहा है, उसकी वजह से सरकार भी बदनाम हो रही है। मुझे पता है कि आज चीनी की देश मे कमी नही और चीनी की पैदावार भी कम नही हुई है। लेकिन जो बडे-बडे पूजीपति और मिल मालिक बैठे है ये जानबूझकर चीनी का अभाव पैदा कर दे रहे है ताकि लोगो को तकलीफ पहुचे क्योकि वे नही चाहते है कि जो आपके प्रोग्राम है वे सफल हो।

पिछले प्लान मे हमने एग्रीकल्चर पर 20 7 परसेट खर्च किया लेकिन दूसरे मुल्को मे फिर भी अनाज मगाना पडा। 160 करोड़ रुपया हम खर्च कर रहे है जो हम दूसरे सूबो को कर्जे के रूप मे दे रहे है। 19 7 परसैट अगर हम सूबो को अधिक दे दे तो हमे बाहर से अनाज न मगवाना पडे अगर पजाब हरियाणा को दे दे जो बहुत पैदावार कर रहे है। अगर हमारी केन्द्रीय सरकार इन सूबो को कुछ मदद दे दे तो अनाज की बहुत बडी समस्या का हल हो सकता है। जितनी हिन्दुस्तान के अन्दर कनक की खपत है उसका 65 परसेट पंजाब दे रहा है। आप देखिए कितना बडा

[श्रीमती सीता देवी]

प्रपोर्शन पंजाब दे रहा है। यह पंजाब जो आपको मदद देता है यह एक किस्म से फारेन एक्सचेंज है। अगर पंजाब इतना न दे तो आपको विदेश मे भीख मागनी पड़े। मै भीख नही माग रही हू, मै वे चीजे चाहती हू जो पंजाब को मिलनी चाहिए और जिनकी तरफ सेन्ट्रल इरीगेशन मिनिस्टर थोड़ा लीनिएन्ट व्यू ले ले या अपने कर्तव्य का पालन कर ले तो समस्या हल हो सकती है।

हमारे यहा बिजली की बड़ी शार्टेज है। बिजली के बिना ट्यूब वेल नहो चल सकते। जब ट्यूब वेल नहीं चलेगे तो खेती नहीं होगी और अनाज नहीं होगा। जो हमारे बहुत बड़े प्राबलम है उनके बारे मे दो-तीन सजेशन देना चाहती हू और उनकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहती हू। थीम डैम का प्रपोजल 64 मे बना, स्टेजेज मे चलता रहा। पिछले साल मीटिंग जम्मू और काश्मीर, पंजाब और हरियाणा की हुई और यह फैसला किया गया कि जो जो ईस्ट पंजाब मे इंजीनियर्स की सीनियारिटी थी उसी के हिसाब मे लगे ताकि यह न हो कि कोई जूनियर आदमी सीनियर बन जाय। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने एग्री कर लिया, मिनिस्टर साहब बीच मे बैठे थे। फिर लोक सभा मे एक सवाल के जवाब मे बताया 27 मार्च को--प्रश्न न० 483--मै इसलिए कोट कर रही हू कि मिनिस्टर साहब देख ले कि मैं गप्प नही मार रही, फैक्ट्स कह रही हू फिर मिनिस्टर साहब ने बताया कि सरकार कन्सीडर कर रही है और जल्दी ही थीम डैम चल पड़ेगा। पंजाब सरकार ने लिखा कि जब यह फाइनलाइज हो गया, फैसला हो गया कि डैम पर सारा खर्च केन्द्रीय सरकार ने करना है तो हमे इजाजत दी जाय ताकि थीम डैम शुरू हो। 64 के बाद 73 हो गया। अगर हमारी केन्द्रीय सरकार थोड़ी मदद दे तो बहुत सारा प्राबलम हल हो सकता है।

हमारी बड़ी देर से डिमान्ड है कि पंजाब मे एटामिक पावर प्लान्ट जल्द लगाया जाय। उससे हमे बिजली मिलेगी। हमने थर्मल प्लान्ट भटिंडा मे लगाया हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय आपको पता है थर्मल प्लान्ट कोयले से चलता है। पंजाब कोयले की खानो से बहुत दूर है। कहा बिहार और कहा पंजाब। कोयले का लाने मे बड़ा खर्च हो जाता है। और इसलिए अगर बिजली बनेगी तो बड़ी महगी बनेगी। तो हमारे चीफ मिनिस्टर ने 13-1-73 को चिट्ठी लिखी कि आप हमे फौरन यह प्लान्ट दे, उसके लिए जगह भी निश्चित कर दी, यह भी लिखा कि एक हजार मेगावाट बिजली पंजाब मे इससे पैदा हो सकती है। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको जल्दी दे दे तो यह काम हो सकता है। फिर क्या हुआ, कहा कि नही कर रहे हैं। लो० सभा मे अन-स्टार्ड क्वेश्चन 604 के उत्तर मे 4 अप्रैल को मिनिस्टर साहब ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट यह सोच रही है कि जल्दी से जल्दी लगाये और इस काम के ऊपर लगाये। इसको वह आज सोच रही है, आज तक क्या नही सोचा।

फिर पंजाब की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने केन्द्रीय सरकार को लिखा कि सौ मेगावाट बिजली जो कोटा का एटामिक पावर प्लांट है, उसमे हमे मिलनी चाहिए। माग की और लोड सर्वे कमेटी और वर्ल्ड बैंक टीम ने यह फैसला भी कर दिया कि पंजाब को इतनी बिजली दी जाए। पंजाब के बोर्ड ने ट्रासमिशन सिस्टम तैयार कर दिया और फरवरी 27, 1970 को पंजाब के एम० पी० मिनिस्टर साहब से मिले और उन्होने यकीन दिलाया कि बिजली आपको मिलेगी। यह 1970 की बात थी, आज 1973 है। फिर 24-12-72 को केन्द्रीय सरकार ने लिखा कि यह अडर कन्सिडरेशन है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने टेलीग्राम दी, उसकी कापी मेरे पास है कि 105 मिलियन यूनिट प्रति दिन कोटा से पंजाब को बिजली मिलनी चाहिए। ये तीन इन्स्टासेज मैने आपके सामने इसलिए रखे है कि अगर हमारी केन्द्रीय सरकार इस जगह से हमको बिजली दे देती तो उससे हरियाणा को भी मिले तो अनाज की जो बड़ी प्राबलम है, पंजाब आगे ही ग्रीन रिवोल्यूशन करता है--उससे सारा अनाज पैदा हो जाता। हम अपने लिए नही माग रहे है। इसमे हमारा स्वार्थ नही है, सारे देश का स्वार्थ है पंजाब तो सारे देश का पेट भर सकता है। इसलिए मै वित्त मंत्री जी से कहती हू कि वे इरिगेशन मिनिस्टर साहब से कहे कि अगर उनके पास ज्यादा काम है तो इस महकमे का कोई और मिनिस्टर ले ले, खुद प्राइम मिनिस्टर ले ले या वित्त मंत्री साहब

ले लें ताकि ज्यादा काम हो सके। तो मेरी ये सजेशन्स हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं अगर मान ली गई तो इस देश में समाजवाद आ सकता है। समाजवाद नारों से नहीं आयेगा अपोजिशन को कहने से नहीं आयेगा प्रैक्टीकल काम करने से आयेगा, जो सुझाव मैंने रखे हैं उन पर अमल करने से आ सकता है।

[THE VICE CHAIRMAN (SHRI V B RAJU) in the Chair]

SHRI BABUBHAI M CHINAI (Maharashtra) Mr Vice-Chairman Sir, I am thankful to you for giving me some time to speak on this very important Bill that is, the Finance Bill Before I come to the Finance Bill, I would like to say a few words about the state of the economy Such an exercise I think, is necessary because the Finance Bill itself has to be framed in that context

It is unfortunate that when the country and the people were expecting an era of prosperity, today we find that there is acute shortage of almost all essential commodities Food, the most crucial consumer item, is not readily available even for love of money This has resulted in riots in a number of places Power cloth cement, paper bricks sugar vanaspati kerosene, edible oil, in fact almost every essential commodity is scarce As a result, prices of these commodities have been rising at a very stupendous rate

In the last one year the general price level has been going up at the rate of more than one per cent per month The situation has been further aggravated by the fact that the number of unemployed has been rising very rapidly For example, the number of applicants on live registers of employment exchanges at the end of December 1972 was 6 9 million compared to 5 1 million a year back All in all it looks that the economy has seriously run down and unless efforts are made to increase production and investment rapidly, both in the public and private sectors, we may be faced with an unprecedented crisis This must be anyhow avoided It is in this background that I submit that Government must seriously consider whether their present fiscal and economic policies and the current programme of taking over the distributive trade are really effective instruments either for economic growth or social welfare

Coming to the Finance Bill let me first thank the Finance Minister for the amendment to the Finance Bill allowing a deduction of tax levied by the State Governments on the agricultural income in computing the agricultural income to be integrated with non-agricultural income for taxation purposes I am, however, of the view that this solves the problem only partially Those in agricultural income tax levying States would continue bearing a heavier load of tax incidence on their combined agricultural and non-agricultural income than those in other States For example, tax liability for a person with a total income of Rs 1,20,000/- comprising Rs 1 00,000/- from non agricultural income and Rs 20 000 from agricultural income would compute to Rs 73,600/- if he is in a State which does not levy agricultural income tax However if he happens to be in a State levying say 30 per cent agricultural income-tax, his tax liability, if computed in accordance with the Finance Minister's amendment would go up to Rs 76,070/, being Rs 70,070/- Central income tax on non agricultural income and Rs 6 000/ State agricultural income tax I am sure the learned Members of the House will appreciate that this is not fair I, therefore, submit that State agricultural levies instead of being allowed deduction from the agricultural income, should be allowed deduction from the tax liability on the combined agricultural and non agricultural income

It is also unfortunate that while on the one hand the recommendation of the Wanchoo Committee in regard to a separate rate schedule for income tax and wealth tax resulting in a sharp increase of tax incidence has been introduced for

[Shri Babubhai M Chinai]

Hindu undivided families, the recommendation of the Wanchoo Committee with regard to the general lowering of the maximum marginal rate of income tax has been altogether ignored I take this opportunity to stress the need for bringing down the maximum marginal rate of income tax and wealth-tax to reasonable levels, if the incidence of tax has not to stifle the initiative and incentive to work and to voluntarily comply with tax laws

I also fail to understand the reason why surcharge on income tax payable by companies should stand on the statute when all other Bangladesh relief levies have been withdrawn After all, this levy was as much a Bangladesh refugee relief levy and introduced during the war-time as others I only want to emphasise that emergency levies should be withdrawn immediately after the emergency is over This not only maintains the public confidence but also keeps the much needed leeway for suitable and swift action in an emergency

Another important matter which I want to point out is about the withdrawal of tax concession in respect of sums paid under contract for deferred annuity containing a provision for the exercise by the insured of an opinion to receive cash payment in lieu of the payment of annuity

This measure may cause unintended hardships to a number of cases particularly the self employed middle class persons who want to ensure a specific amount handy at the time of their retirement With a view to meeting such cases, I submit for the consideration of the hon Finance Minister laying down a certain limit, say, up to Rs 2 lakhs in respect of which tax benefit should continue in spite of cash option Besides, the proposed provision has to be effective for the assessment year commencing on 1st April, 1974 This will obviously cause hardships to those who have taken out policies before 28th February, 1973, and are liable for assessment year in 1974 75 Such assessees will be deprived of the tax benefit which in my view, is not equitous I therefore urge that the new provision apply only to policies taken out after 28th February, 1973

The Finance Minister has sought to amend the definition of the term 'short-term capital asset' so that a capital asset held by a person for not more than 60 months immediately preceding the date of its transfer will be treated as a short-term capital asset and the gains arising on sale or transfer of such asset will be taxed as ordinary income In my view, subjecting to tax, in one year, at sharply progressive rates of tax, gains developing over a period of five years, is not fair Such gains are mere artificial gains reflecting the fall in the value of money Most countries treat assets held beyond six months to two years as long term capital assets and the gains arising therefrom are either totally exempt from tax or are taxed at concessional rates I am therefore not in favour of increasing the period of holding an asset from 24 months to 60 months for an asset to qualify as long held asset However, if a change in this respect is deemed necessary I suggest that the basis of taxation of capital gains may be so rationalised that the capital gains arising from transfer of assets are taxed at the rates which have some relation to the period during which the asset is held In this regard I also want to point out that the provision as proposed will be effective from the 1st of April 1974, and would thus cause avoidable hardship to those who effected transfer of capital assets before 28th February 1973, and as per their previous year are liable to tax for assessment in respect of the transfer in assessment year 1974 75 Such assessees, it may be appreciated, could not foresee the change to take the tax element into account while effecting the transfer. I therefore submit that it will be equitable if it is provided that the provision shall not apply to transfers effected prior to 28th February, 1973

I also do not see any justification in taxing the amount received as compensation for taking over management of any

business by Government It has to be appreciated that management is taken over by Government not at the volition of the assessee Besides the assessee may have to incur a variety of expenses out of the compensation received Subjecting the compensation money to tax as income from profits and gains of business is therefore, in my view, not equitable The amount being in the nature of capital receipt should be excluded from the purview of tax If, however the management compensation is to be taxed it should at least be treated on par with compensation for termination of managing agency That is, 25 per cent of the compensation money should be allowed deduction for computing the taxable income as in section 80 S of the Income tax Act

May I also say a word about the initial depreciation allowance likely to be proposed soon as an alternative to the development rebate? It has been stated by the Finance Minister that it would be applicable only in respect of selected industries In my view, since the development rebate was available to all industries initial depreciation should also be made available to all industries

I suggest that at least for priority industries and industries in backward areas, some additional depreciation allowance is essential

I welcome the proposal of the Finance Minister to give incentive to development of backward areas However, I feel that this benefit will be extremely limited in scope and the advantage of the incentive will not be available to all regions where development has to be fostered I would suggest that the definition of backward area" should be liberal enough to make all regions benefit from the scheme

Lastly, let me now say a few words about indirect taxation I would emphasise that the 40 per cent import duty on cotton is unrealistic and prohibitive Already the mills are increasingly using indigenous cotton This is good so far as it goes but it does not enable the smaller people to get yarn at reasonable prices nor do the consumers get cloth anywhere near fair prices The sharp spurt in the price of textiles since August last is unprecedented in the history of India

The Yarn Control Order is also contributing to the rise in prices Although the Central Government has not asked the State Governments to oust the normal trade the latter have done so with the result that the smaller weavers are not getting yarn at all

I am glad that the Finance Minister has already announced some concession in the Customs duty on black and white raw cinematograph films reducing it from 50 to 30 paise per linear metre However I have been informed that even a duty of 30 paise per linear metre will be too heavy a burden for the film industry to bear Further a 5 per cent *ad valorem* auxiliary Customs duty will also have to be paid Even now the film industry is going through a period of strains and stresses Many of the producers who were once investing lakhs and lakhs of money on a film have now started economising in their investment This is mainly because on the one hand the cost of production has gone up and on the other due to keen competition they are not getting adequate return on investment They have not only to pay huge amounts to the stars but also to the studios and the distributors I therefore, strongly urge that the recent increase in import duty on raw cinematograph films should be completely withdrawn

The policies followed by the State and Central Governments are unco ordinated Distribution of yarn and distribution of wheat and rice are the recent examples While it is said that the Central Government would want only the take over of wholesale trade in wheat and rice, some State Governments have already disrupted the retail trade also, for example, in the city of Bombay Thank you

[Shri Babu Bhai M. Chinai]

SHRI S. S. MARISWAMY (Tamil Nadu): It is a good augury, Mr. Vice-Chairman, Sir, that our Finance Minister is physically present to-day to listen to this debate. I hope, after listening to the debate, he will in his reply show some concessions to the suffering masses. Sir, after the presentation of the Budget, the prices of foodgrains, edible oils and other bare necessities of life have risen, up to now, by 25 to 27 per cent. This is not a tall statement that I am making without any basis. I would ask the hon. Finance Minister to depute a trustworthy man, a man who is in his confidence, to go to any bazar, in Delhi or in any other place, and find out to what extent the prices have shot up. The price of everything has shot up. And if at all there is anything cheap, it is, I am sorry to say, corruption. Corruption is the cheapest commodity now in the country. It may surprise you, Sir, to think how people are living in this country. A man who was spending Rs. 25 on groceries six months before has to spend now Rs. 80. What is the increase that he has got in his emoluments? Not even a pittance of five rupees And how do you hope that the ordinary people will get along? The prices of foodgrains, oil, vegetables, everything has gone up. The Finance Minister said the other day that he had, for the good of the country, levied excise duty on cigarettes, tobacco, etc., etc. But finally the whole thing comes on the head of the common man. Now cigarettes and tobacco are taxed but nobody in our country is a saint.

I believe even our Finance Minister smokes and he has to pay and he can afford to pay....

SHRI MAHAVIR TYAGI: No, he does not smoke.

SHRI S. S. MARISWAMY: But what about the rest of the people? If you go to any workshop, any coal-mine—unfortunately Mr. Kalyan Roy is not here; he can tell us about coal-mines—any factory, you will find that people, whenever they get hungry, take more of tea or cigarettes or beedis. It quenches their hunger. Invariably everyone of them goes either for tea or for a cigarette or a beedi in order to quench his hunger. This has become a fashion. So, by levying these taxes you are not helping the poor. If you tax cigarettes and other things, then certainly this tax is going to fall on the common man.

Then about unemployment. No serious attempt has been made to solve the unemployment problem. In 1971 the figure was 45 lakhs. In 1972 the figure of unemployed people rose to 57 lakhs. And now, I understand, it is more than 1 crore odd. And what is it that the Government is going to do? Unfortunately we have witnessed today food riots in Nagpur which is a part of the Finance Minister's State. In his neighbouring State, Gujarat, also there was a food riot. I heard some stories from Nagpur. The stories were horrible. I really shudder to think as to what is going to happen to this country if similar things happen in all parts of the country and if no drastic measure is taken to solve the sufferings of the people. An entire family, the mother, the father, the children and all other dependents, have to go and stand in queue in front of the ration shops to get their rations and unless and until they do so, they are not given their ration. And what is the quantum of the ration they get? Four ounces of wheat is given per head per week. Now, how can you expect people to live with four ounces of wheat a week? In Madras in 1952 six ounces of rice were given. That was a slogan to bring down the Congress. In those days if any man walked on the road wearing khadi, people used to heckle him saying, "Oh! six ounces, you are going". That slogan alone brought down the Congress rule in that State. After all your so-called green revolution, after all your trumpeting that you have achieved self-sufficiency, with your slogan of *garibi hatao*, after the so-called dynamic Ministry has come into power, what have you achieved? Now people have to go and stand in queue for four ounces of wheat per head per week in Nagpur and other places. And by the time half the queue is

finished, you declare stocks are exhausted and you start closing the shutters. In this situation if people naturally get agitated, helpless, and if there is disturbance, immediately you call the police and lathi charge is done. This is what happened actually at that place. I am subject to correction. This is what I heard. In the lathi charge and police firing many precious lives were lost. I cannot understand why a country, after 25 years of independence, still depends for foodgrains upon foreign imports. It is a shame. This Government has thoroughly failed. I do not blame our Finance Minister. I know he is a good man. But what is the entire Cabinet doing? Where have our Plans gone? If the people cannot get two morsels of food, then there is absolutely no use of this Government existing. There is anarchy. *(Interruption)* You are going to bring a chaotic condition and I do not know where it is going to lead to. This situation is a very alarming situation. I want the Finance Minister to bestow his immediate attention on this problem. Secondly, about educated unemployed. That figure also is very high. In 1971 the figure of educated unemployed was 27 lakhs. Now it is 60 lakhs. It is like giving a knife in the hands of a child, letting loose the educated unemployed in the country. A child does not know how dangerous it is to play with a weapon. In the same manner, if the educated people are not given jobs, they will sit and go on thinking which may lead to many undesirable things. Many revolutions have been started by the educated unemployed people.

I may not get surprised if something happens in the country and the wind is also blowing in that direction. After what has happened in the Supreme Court, I doubt very much whether we have any orderly system in the country. For example, today I was really shocked when I read a news item. I did not know whether I was in India or in Romania or, for that matter, in some other country. This is today's Hindustan Times edited by a pro-Congress Editor and owned by a group which supports Congress. Workers can 'wrest' favourable verdicts. This is double column heading given to the news item. I will read the relevant portion.

> "Addressing the workers of the INTUC-led Rashtriya Mill Mazdoor Sangh here (that is, Bombay), he said, (that is, Mr. Shankar Dayal Sharma)...

AN HON. MEMBER: He is a Doctor.

SHRI S. S. MARISWAMY: I stand corrected. Dr. Shankar Dayal Sharma said:

> "If the workers are well organised, no judge will dare to give an anti-labour decision in future". (The word 'dare' is to be underlined).

Is it right for the Congress President, the head of the Congress organisation nursed by Mahatma Gandhi who was the apostle of truth and who believed in non-violence...

SHRI BIPINPAL DAS: Mahatma Gandhi used stronger words.

SHRI S. S. MARISWAMY: I do not know what you are referring to. I have also read Gandhiji and I also followed him until his death. He never said in this way.

> "Dr. Sharma referred to the preventing of some advocates from attending the Supreme Court on May 3 when the Bar Association observed the bar "solidarity day" and remarked "the workers can also prevent the counsel of the employer from attending the court".

He wants the workers to enter into the court, find out who is going to appear for the employer, catch hold of him and gherao him or assault him or God knows what he wants to be done to him. He is a Doctor and so he knows what. He goes on further:

> "In such an event (that is, when the workers catch hold of that lawyer), the Police should not intervene when the Advocates were obstructed while proceeding to the Supreme Court".

Then he goes on in his own way....

AN HON MEMBER The Advocates of whom you talk have taught them how to get hold of a Judge and push him out of the Chamber

SHRI S S MARISWAMY One wrong does not justify another wrong There the Advocates have done something Here Dr. Sharma is asking workers to go to the court and prevent the lawyer appearing for the employer from appearing Dr Sharma is the leader of a responsible organisation of the ruling party And he speaks like an ordinary soap-box orator and an ordinary third-rate politician He is the man under whom our Chavan is working Does he accept him as his leader?

I am really amazed that things are happening in a manner that is not at all good to the country.

For example, this is a book written by a reputed journalist, Shri A G Noorani I believe he hails from Bombay and that the Finance Minister knows him He is a good writer He has written a book and this is an article wherein he has brought out a secret document written by my good friend, Shri Kumaramangalam in 1964

In his 64-page thesis he says like this

"The bourgeoisie yet heads the Indian National Congress which was the organisation of the United National Front that led the struggle for Indian freedom Supporting the Congress even today are large sections of the petty bourgeoisie, the major part of the working class These sections follow the bourgeoisie Congress leadership, not because they support that leadership's real programme of developing capitalism in India, but because they are supporters of the proclaimed programme of the Congress—the Jaipur, Avadi and Bhubaneswar decisions of the Congress to build 'socialism' "

Then, Sir, he goes on to say

"The Communist Party would be ready to support the Congress and even to participate in a United National Government if the Congress would implement its own proclaimed policy, and the Communists would join all democratic elements to build a mighty mass movement "

Then, about the transfer of power on the 15th August, 1947

"On August 15, 1947, power was transferred from the British imperialists to the representatives of the National United Front namely, the bourgeois leadership of the Indian National Congress'

That is power was transferred to nobody else but to Shri Jawaharlal Nehru, the acclaimed leader of the Indian capitalist bourgeoisie section' Then, Sir, he goes on saying

SHRI BIPINPAL DAS Sir on a point of order

SHRI S S MARISWAMY. Please wait I am coming to the subject

SHRI BIPINPAL DAS Sir, I want to raise a point of order

SHRI S S MARISWAMY: Please wait a minute I am coming to the point

SHRI BIPINPAL DAS Sir, what relation has it got with the Finance Bill?

SHRI DAHYABHAI V. PATEL (Gujarat) He is entitled to say that on the Finance Bill You better read the Rules.

SHRI S S MARISWAMY. Then he goes on to say, Sir, like this "Use the Congress to share its power and then oust it" He goes on to say, "in the last analysis, the decisive force can only be the Communist Party"

Sir, Shri Kumaramangalam might have joined the Congress. But I wonder whether he has changed his view. I do not know whether he joined the Congress as a tactical measure or with a genuine desire to serve Indiraji... (*Interruptions*) And Sir, the CPI supports the Congress, Sir, there is a quotation of Lenin: "I support such things as the rope supports a man who is being hanged". This is what is being done, what is happening, to get the support of Shri Mohan Kumaramangalam. The Supreme Court case is one step. Now, Shri Shankar Dayal Sharma, the Doctor, has given a call to the labour section to wrest favourable verdicts. I really shudder to think as to what is happening in this country. Is there any meaning in retaining the emblems bearing the words "Satyameva Jayate", the Ashoka Pillar and other symbols all over the country? You can in one sentence say: "Look. This is our Constitution". Or, you can say, "We have no Constitution. Our Constitution is whatever Mr. Kumaramangalam says or Mr. Gokhale says or whatever this man says or that man says". You can make it clear. We have got a Constitution. Whenever it suits you, you quote the Constitution. Whenever it suits you, you say that the Constitution should be respected. Otherwise, you do not worry about the Constitution. This sort of double standards must come to an end. I know Mr. Chavan belongs to the older section of the Congress who has done yeoman's service to the cause of freedom and I know, if contacted privately, he will condemn Dr. Sharma's views. But he cannot open his mouth now because himself and other nationalist elements in the Congress are prisoners in the hands of Mr. Kumaramangalam and other people.

Sir, a day will come—take it from me—when all these Ministers would find it difficult to speak to their own Secretaries. If they want to speak to their Secretaries and pass some orders, it will have to be routed through Mr. Kumaramangalam or Mr. Gokhale and that day is not far off. We have seen what happened in Eastern Europe soon after the War. The Communists joined hands with all the parties even of the capitalists, and as Mr. Kumaramangalam has said, in the last analysis, everybody would disappear and the Communists alone will be there like the Gundhara about whom we have read in our mythology.

Sir, I hope I have driven home the point and that the Government will consider them and do something about them. Thank you, Sir.

कमलनाथ झा (बिहार) · उपसभाध्यक्ष जी, इस सदन मे आज मै पहली बार बोलने के लिए खडा हुआ हू और बोलने से पहले जब मेरी दृष्टि घडी की ओर जा रही है तो मै देखता हू कि पाच बजने मे सिर्फ दस मिनट ही बाकी है···

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : हम 6 बजे तक बैठेंगे।

श्री कमलनाथ झा : जब कभी अपने देश में राजनीति करवट लेती है तो उस की कुछ प्रतिक्रिया तो होती है। यह प्रतिक्रिया आज ही नही दिखाई पड रही है, बल्कि हिन्दुस्तान को आधुनिक राजनीति की जब से शुरुआत हुई है उस समय मे ही यह प्रतिक्रिया दिखाई पड़ती है। जब काग्रेस को हमारे स्वर्गीय राष्ट्रपिता ने एक क्रान्तिकारी मार्ग पर अग्रसर किया तो चाहे वह वामपथी हो या दक्षिण पथी, दोनो तरह के लोगो ने कहा था कि वे इस देश को रसातल मे पहुचा देगे। जब 1942 को महाक्रान्ति हुई और अग्रेजी हकूमत से हिन्दुस्तान की जनशक्ति टकरायी तो जितने बुद्धिजीवी थे हमारे एक कदम पीछे हटने पर, उन्होने कहा कि गाधी जी और जवाहरलाल जी ने देश को सौ कदम पीछे हटा दिया। लेकिन बाद मे इन लोगो ने देखा कि 1947 को रात 12 बजे दिल्ली के सिहासन पर से यूनियन जैक नीचे उतारा गया और उसके स्थान पर तिरगा लहराने लगा। जब कास्टीट्यूएट असेम्बली की बैठक हुई तो जो स्वराज्य जनता की मदद से प्राप्त किया गया था उसको जनता तक

[श्री कमलनाथ झा]

ले जाने के लिए हमारे तत्कालीन नेताओ ने घोषणा की कि जनता के बल पर हमे राजसत्ता प्राप्त हुई है और बालिग मताधिकार द्वारा हम जनता को सत्ता सोप देगे। इस पालियामेंटरी डिमोक्रेसी को इगलैंड ने जन्म दिया वहा के क्रातिकारियो और वहा के मानवतावादियो को भी इतना साहस नही हुआ कि वे यूनिवर्सल सफरेज का एलान करते और आज से केवल पाच साल पहले वहा महिलाओ को बालिग मताधिकार दिया गया है। लेकिन हमने जिस दिन कास्टीट्यूशन लिखना शुरू किया उसी दिन हिन्दुस्तान के तामाम बालिगो को चाहे वह पढे हो या अनपढ हो, चाहे वह द्विज हो या शूद्र हो, चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान, हमने सभी को बालिग मताधिकार दिया। नयी करवट ली हिन्दुस्तान की राजनीति ने और इस अवसर पर भी बडे-बडे विद्वानो ने, बड़े लोगो ने और बडे समाज चिन्तको ने कहा कि ऐसी डेमोक्रेसी से हिन्दुस्तान बर्बाद हो जाएगा। हिन्दुस्तान की सरकार नही चल सकेगी, लेकिन हमारे जनतत्र की भी परीक्षा हुई सब्जेक्टिव एव आब्जेक्टिव विदेशियो ने आक्रमण किया, चीनियो ने और पाकिस्तानियो ने हिन्दुस्तान का बच्चा-बच्चा विदेशी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए खडा हो गया। यह हमारी पोलिटिकल कासेसनेस थी और जब देश मे लोगो ने हिन्दुस्तान के टुकडे-टुकडे करने की साजिश की तो हमारे जनतत्र ने सिद्ध कर दिया कि कोई भी इस देश के टुकडे नही कर सकता है। हिन्दुस्तान के 50 करोड लोग इसके प्रहरी है। आज हिन्दुस्तान मे शक्तिशाली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और राज्यो मे स्टेबिल सरकारे है। हमारी सरकारे जनता के वरडिक्ट पर खडी हुई है। फिर तीसरी करवट हिन्दुस्तान की राजनीति ने ली। प्रतिक्रियावादी शक्ति से प्रगतिशील शक्तियो का टकराव हुआ। नई शक्ति उभर कर सामने आई। कराची काग्रेस से लेकर बम्बई काग्रेस तक की यात्रा मे जनता को जो आर्थिक अधिकार एवं सामाजिक न्याय देने का वायदा किया गया था। हमने उसको अमली जामा पहनाने का बीड़ा उठाया है और वह है गरीबी मिटाना। आज फिर जिस तरह से हमारी आजादी की लडाई का मखौल उडाया गया था, जिस तरह से जनतत्र की स्थापना का बालिग मताधिकार का, मखौल उडाया गया था, उसी तरह से एक बार फिर हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसैल्फ बट आन दि अदर प्लेन, लोग गरीबी मिटाने की लड़ाई का मखौल उडा रहे है। जिन लोगो ने आज तक हमारा मखौल उडाया था, इतिहास ने अब तक उनका मखौल उडाया है और हमे विश्वास है कि इतिहास फिर एक बार उनका मखौल उडायेगा। मै कहना चाहता हू कि हिन्दुस्तान जनतात्रिक ढग से, पालियामेंटरी ढग से, डेमोक्रेटिक तरीके मे, सोशलिज्म की ओर बढ रहा है। गरीबी तो हटेगी। बुनियादी सवाल है कि कैसे हटेगी ? इगलैंड ने इडस्ट्रियल रिवोल्युशन किया, जर्मनी ने इडस्ट्रियल रिवोल्युशन किया, फ्रास ने इडस्ट्रियल रिवोल्यूशन किया। कैपिटल फार्मेशन कहा से हुआ। इन देशो मे कैपिटल फार्मेशन इसलिए हुआ कि ससार के बडे भूभाग को इन्होने दबोचा। उपनिवेश बनाया और वहा से रा-मैटेरियल इकट्ठा किया और जब इससे भी काम नही चला तो आजादी की लडाई के वक्त मे हमने पढा "अवध के नवाब के घर मे किसने डाका रात को डाला था और वाजिद अली शाह के घर का तोडा किसने ताला था", हमारी दौलत कालोनियल रूलटम से लूटी गई और जब इससे भी काम नही हुआ तो रानी एलिजाबेथ के रेन मे हाकिन्स और ड्रैक ने हाई-सीज मे लूट-पाट की। इतिहास जानता है कि अमेरिका ने किस तरह से स्लेव्स लेबर का एक्सप्लायटेशन कर के कैपिटल फार्मेशन किया। जो डिक्टेटरशिप आफ दि प्रोलेटेरिएट के देश है, चीन और रूस, उसमे वाइट-टेरर एड रेड-टेरर की बात इतिहास अभी तक भूला नही है। लेकिन न हम स्लेव का एक्सप्लायटेशन चाहते है, न हम उपनिवेशवाद चाहते हैं, न हाई-सीज मे एलिजाबैथ के सी-डाग्स की तरह लूट करना चाहते है और न डिक्टेटरशिप आफ दि प्रोलेटेरिएट की तरह से मनुष्य को यत्र बना कर कैपिटल फार्मेशन करना चाहते है, बल्कि मानवता की रक्षा करते हुए, मानव स्व-

स्वतन्त्रता की रक्षा करते हुये, कठिनाइयो से झूझते हुये हम अपने कैपिटल फार्मेशन का एक अभिनव प्रयोग कर रहे है। आज अगर थोडी सी मूल्य मे वृद्धि हो जाती हे .

श्री ना० कृ० शेजवलकर : थोडी सी ?

श्री कमलनाथ झा : अच्छा, अधिक ही मूल्य बढ जाता हे । अगर मूल्य बढ जाता है तो वह इसलिए कि हम 50 करोड आदमियो को सुख पहुचाना चाहते है। कुछ लोग प्रगति चाहते है, लेकिन प्रगति के लिये परेशानी उठाना नही चाहते है। परेशानी उठाये बिना प्रगति असभव है। अगर हम प्रति व्यक्ति 25 हजार रुपये की पूजी इनवेस्ट करेंगे तब कही लोगो की कुल आमदनी चार सौ रुपया या पाच सौ रुपया या तीन सौ रुपया प्रति माह होगी। करोड आदमियो के लिए इतनी आमदनी, इतनी इनकम कहा से लायेंगे, जब तक कि बडी तादाद मे हम कैपिटल इनवेस्ट नही करेंगे। आज ससार मे जो पूजी के ठेकेदार है, वह कहते है कि तुम हमसे पूजी लो लेकिन तुम अपनी आजादी हमारे पास गिरवी रखो। हमने खून की कीमत से आजादी पाई है, हम उसको रुपये की कीमत पर गिरवी रखना नही चाहते, हम अपनी जनता को जानवर भी नही बनाना चाहते (डिक्टेटरशिप आफ दि प्रोलेटैरिएट) तो बताइये कैपिटल फार्मेशन कैसे होगा ? गरीबी कोई नारे से नही हटेगी। आप भी कहते है, हम भी कहते है। इसका एक ही वे-आउट है। अगर हम कष्ट नही उठायेंगे, अगर हम टैक्सेशन नही करे, अगर हम अपनी बेल्ट को टाइट नही करे, तो ससार मे कौन हे जो कि कुबेर का खजाना ला कर हिन्दुस्तान को बाट देगा और उस खजाने से हम अपनी गरीब जनता की आमदनी 200, 300 या 400 रुपये की कर लेगे, इतनी मिनिमम इनकम हम एश्योर करेंगे।

5 P. M.

इसलिए हिन्दुस्तान को अपने इन्टर्नल रिसोर्सेज के बल पर, जनता की मेहनत के बल पर अपनी खुशहाली की इमारत खडी करनी होगी। मै सुन रहा था, एक मेरे मित्र कह रहे थे कि अमेरिका भारत को चेन थाप फर्टिलाइजर फैक्टरी दे रहा था। एक बहुत बडे काग्रेस के नेता थे, अभी वह सगठन काग्रेस मे चले गये हे, वे कहते थे कि पी० एल० 480 मे जब सस्ता गेहू मिल रहा है तो हिन्दुस्तान मे गेहू पैदा करने की जरूरत क्या है ? हिन्दुस्तान पी० एल० 480 मे गेहू ले आय, भोजन और भोजन की पैदावार के लिए अमेरिका या अन्य राष्ट्रो पर निर्भर रहे तो हिन्दुस्तान आजाद रहेगा या गुलाम होगा ? यह हमारा हिन्दुस्तान होगा या खाना देने वालो का हिन्दुस्तान होगा ? इसलिए हम पूजीवादी एव तानाशाही दोनो मार्गो के विरोधी है। न हम पूजीवादी रास्ते से दूसरे के खून को चूस कर, दूसरो को गुलाम बना कर अपनी इमारत खडी करना चाहते है और न अपनी जनता को बेडियो मे कस कर, हाथ मे हथकडी और पेर मे बेडी डाल कर समाजवाद बनाना चाहते है। जैसा मैने शुरू मे अर्ज किया, हमारा एक अभिनव प्रयाग हे। क्या होगा, हम नही जानते। हमको गीता के उस श्लोक की तरह—कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन—एक अभिनव प्रयोग करना है, जिसमे डेमोक्रेसी भी हो, जिसमे सोशलिज्म भी हो। ऐसा प्रयोग आज तक ससार मे कही नही हुआ। इसलिए हम अपने मित्रो से कहते है, अगर आपको राष्ट्र से प्रेम है, अगर आपको हिन्दुस्तान मे प्रेम है, अगर आपको डेमोक्रेसी से प्रेम है, अगर आपको गरीबो से हमदर्दी हे तो आपको हमे सहयोग देना चाहिए। इस राष्ट्र निर्माण के यज्ञ मे अगर आप सहयोग नही देगे तो आप याद रखे हिन्दुस्तान की गरीब जनता अपनी गरीबी तो मिटाएगी, लेकिन आने वाले इतिहास मे आपका नाम उसी लिस्ट मे लिखा जायेगा जिस लिस्ट मे आजादी की लडाई का विरोध करने वालो का लिखा गया था।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इन चद प्रारभिक शब्दो के साथ आपके माध्यम से अपने माननीय वित्त मत्री जी का ध्यान एक विशेष समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हू। आखिर आजादी के पच्चीस वर्षो मे, इस स्वराज्य के पच्चीस वर्षो मे, जो समाज का स्वरूप आज तक खडा हुआ था उसके खिलाफ बगावत करके हमने एक नए

[श्री कमलनाथ झा]

मार्ग का अनुसरण किया है। वह मार्ग है देश से गरीबी मिटाने का मार्ग। यह गरीबी दरअसल है कहा पर? इट मस्ट बी लोकेटेड फर्स्ट। इसको पकडना होगा। ठीक है, सरकारी कर्मचारियों को कठिनाई है, लेकिन आप यह नही कह सकते कि सरकारी कर्मचारियो के लिए कुछ नही हुआ। कारखाने मे काम करने वाले मजदूरो को भी कठिनाई है, लेकिन आप यह नही कह सकते, कोई पार्टी यह नही कह सकती कि उनके लिए कुछ नही हुआ। आज बडे-बडे और माध्यम काश्तारो को भी कठिनाई है, उचित दाम नही मिलता है, लेकिन सरकार ने उनके लिए भी बहुत कुछ किया है। लेकिन एक तबका है हिन्दुस्तान मे और वह सबसे बडा तबका है। वह सबसे गरीब है और मै समझता हू कि उसकी ही गरीबी से प्रभावित होकर श्रीमती इन्दिरा गाधी और आदरणीय नेता चव्हाण ने काग्रेस मे भी अगर टूट करने की जरूरत पडी तो किया और वह है हिन्दुस्तान के गावो मे बसने वाले 17 करोड खेतिहर मजदूर। आज जो इडस्ट्रियल लेबर है उसके लिए हमने सिक्योरिटी आफ सर्विस दी है, उनकी नौकरी कोई छीन नही सकते है। नम्बर 2, उनको बोनस दिया, 4 परसेन्ट के बदले 8 परसेन्ट, आपके यहा लाभ भी हो तो। काम करने के समय अगर उनकी अगुली कट जाए तो वर्कमैन्स कम्पेन्सेशन एक्ट उनके लिए बनाया गया है, वे रिटायर करे तो ग्रैचुइटी और प्राविडेन्ट फण्ड की फैसिलिटी उन्हे दी गई है और अगर वे बीमार पड जाए तो एम्प्लायीज स्टेट इन्श्योरेन्स कारपोरेशन की मार्फत उनके पीछे 5,000 रु० भी खर्च करना पड तो किया जाएगा। यह सब होना चाहिए, इससे अधिक होना चाहिए। लेकिन वह मजदूर जो गावों मे काम करता है, खेतिहर मजदूर, उसकी वर्किंग कडीशन कैसी है? आसाढ मे चिलचिलाती धूप और भादो मे उमडते हुए आसमान के नीचे वे काम करते है। लेकिन उनके लिए कोई एम्प्लायमेंट की गारटी नही। वे छ महीने काम करते है और छ महीने बेकार रहते है। उनके लिए आज तक इम्प्लाइज स्टेट इश्योरेंस कारपोरेशन की स्कीम नही है तथा उनको इन 25 वर्षों मे सल्फागुलाइडिन और इन्ट्रोकिनोल जैसी साधारण दवा तक नही मिल सकी। उनके लिए आज तक प्राविडेन्ड फड की व्यवस्था नही की गई और न ही पेंशन की कोई गुजाइश की गई। सारे भारत मे आज किसानो का नाम लिया जाता है, लेकिन खेती मे जो कमौनी करता है, जो रोपा करता है, जो कटनी करता है, जो उसावन करता है, उसको किसान नही कहा जाता है, बल्कि जो सुपरवाइजर है उसको किसान कहा जाता है। जो वास्तविक खेती करते है उन्हे किसान न कह कर किसान उन्हे कहा जाता है जो खेतो मे काम नही करते है। इसलिए मैं समझता हू कि हम लोगो ने गरीबी को हटाने का जो व्रत लिया है, जो उसके लिए प्रोग्राम बनाया है, उसके सम्बन्ध मे मै यह निवेदन करना चाहता हू कि गाधी जी यह कहा करते थे कि अगर देश के लिए कोई योजना बनानी हो तो हिन्दुस्तान के सबसे अधिक गरीब आदमियो को सामने रख कर योजना बनाई जानी चाहिए। हम अब पाचवी योजना तैयार करने जा रहे है और इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इस दृष्टिकोण को उन्हे अपने सामने रखना चाहिए। मै अपने क्रान्तिकारी वित्त मत्री जी से निवेदन करना चाहता हू कि हर राज्य मे और केन्द्रीय स्तर पर भी एक ऐसे मत्री की नियुक्ति की जानी चाहिए जिन के जिम्मे केवल खेतिहर मजदूरो का ही विभाग हो। जिस तरह से ट्रेड यूनियनो का एक आर्गनाइज्ड सेक्टर है, जिस तरीके से इडस्ट्रियल लेबर्स को अधिकार दिये गये है, उसी तरह से खेतिहर मजदूरो को भी अधिकार मिलने चाहिए।

सब विरोधी पार्टिया कहती है कि हमारी हमदर्दी खेत मजदूरो के साथ है। मै आपके सामने बिहार के आकडे रखना चाहता हू और निवेदन करना चाहता हू कि बिहार की कुल आमदनी 110 करोड रुपया है और यह सब सरकारी कर्मचारियो पर खर्च हो जाती है। इस तरह से सरकार की जितनी भी आमदनी है उसके बेनीफिसियरीज करीब 25, 35 प्रतिशत

लोग ही हैं। आज हमारे यहां जो हरिजन है, आदिवासी है, और पिछड़ी हुई जाति के लोग है, उनको आम तौर पर फायदा नही हुआ है। इसके जो लीडर है, जो नेता लोग हे और जो कुछ और होशियार लोग है उनको भले ही फायदा हुआ हे और मासेज पिछड़ी हुई ही है। जाति के नाम पर समाज के दलित एवं उपेक्षित वर्ग को ऊपर उठाने का पुराना तरीका बकार सिद्ध हुआ हे इसमे व्यक्ति विशेष को लाभ होता है और समाज जहा का तहा रह जाता है। अत, सम्पूर्ण हरिजन, आदिवासी तथा पिछड़ी जातियो का एक हिस्सा जो पेशे से खेत मजदूर है उनको पैसे के आधार पर सगठित करना उनकी रोजी रोटी एव सामाजिक उत्थान का नवीन अभियान आरभ करना 'गरीबी हटाओ' कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण अग होना चाहिए। ऐसा करके ही हम अपने घोषित लक्ष्य की पूर्ति कर सकेंगे।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मै आपको धन्यवाद देता हूं।

SHRI HAMID ALI SCHAMNAD (Kerala): Mr. Vice-Chairman, Sir, while supporting the Bill introduced by Mr. Chavan to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 1973-74, as passed by the Lok Sabha, I should like to bring to the notice of the Finance Minister the clubbing of Central income-tax with agricultural income. Agriculture income varies from State to State and some of the States have already levied a heavy taxation. As far as Kerala is concerned, a farmer who has got a gross agricultural income of Rs. 5,000 is being taxed, whereas in some of the States to the extent of Rs. 20,000 they have been exempted. As far as Kerala is concerned, a farmer who has got an income of Rs. 5,000 is exempted, but if he has got an income of Rs. 5,100 then he has to pay agricultural income-tax and it also goes by the slab system, and a stage comes that a farmer has to give 60 per cent of agricultural income-tax. Apart from this, he has to pay the plantation tax, land revenue and also as far as Kerala is concerned, if a farmer grows paddy, wheat or cholam, whatever it may be, his income comes into the picture and he is being levied. A small farmer who has got an income of Rs. 10,000, if he happens to have a non-agricultural income somewhere, then both the incomes will be clubbed together and he will be taxed heavily. If that is so, rural economy will be effected, and the rural people who are just coming up with scientific cultivation, modernisation of agriculture now, they have also been taxed very heavily. Of course, the Finance Minister was good enough to make some remissions, but that is not enough. As far as agricultural income is concerned, that should not be left to the Central income-tax, it should be left to the State concerned, the State should levy it.

Another point is, I am glad that the Government's attention has been paid to the uplift of the backward regions. Special attention is being paid and I welcome that move. At the same time, I draw the attention of the Government to the imbalances of the different communities. I am referring to the Muslim community, a minority community. They do not get into services, they do not get a fair play in the different walks of life. In this connection, I draw the attention of the Government to the illustrated Weekly of India of April 22, 1973 which has recently published an article. I read from page 8—

> "As a test-case, let us take the simple but vital matter of jobs under the Government. There is no doubt that unemployment afflicts all sections of Indian society. The poor among the Hindu majority are not much better off than most Muslims; they are perhaps in a far worse position than the offspring of rich and influential Muslims with right connections and the necessary pull."
>
> But when all is said and done, there can be no escape from the stark reality that the share of the Muslims in public employment is abysmally low. Up-to-date figures are, alas, not available. But it does seem shocking that, in 1965,

[Shri Hamid Ali Schamnad]

there should have been only 111 Muslims out of more than 2100 IAS officers; around a dozen Muslims out of 270 members of the Indian Foreign Service; and a mere 43 Muslim officers out of 1,200 in the Indian Police Service! It is doubtful if the position is very much better today because, in 1972, only one Muslim—precisely one—got selected for the three All-India services!

Incredible though it may seem, according to the latest available statistics (1965), there were only six Muslim officers in the top two grades of the CSS out of 681. In the next grade, there were only four Muslims out of 2,000. As if this is not shocking enough, there were only 21 Muslims out of 9,900 clerks.

Who can blame the Muslims for feeling that some deep-seated prejudice is at work against them?"

And so many other things are here. These should be taken into consideration. After all, the *Illustrated Weekly* s not an organ of the Muslims of India, nor is it an organ of the Muslim League. But even the *Illustrated Weekly* has given some statistics. I do not know how far they are correct. Anyhow it is for the Government to study this matter. The Prime Minister was good enough to make statements in the House and outside the House that special attention will be paid to give employment to the educated Muslims and that they would not be discriminated against. But giving these statements one after another is not going to help the community as a whole. So, I appeal to the hon. Finance Minister and the Government to see that Muslims are taken into confidence and some seats are reserved for them. They should be declared as a socially and educationally backward community, as it is being done to-day in Tamil Nadu and Kerala. In these two States, Muslims have been declared as a socially and educationally backward community. This is not against the Constitution because the Supreme Court has held that on religion alone, you cannot reserve a seat. For that, a commission was set up in Kerala and that commission went into the matter and found that the Muslim community is backward as far as education is concerned and as far as employment is concerned. So, it is on this basis that reservations have been made. I appeal to the Finance Minister to make use of his good offices and see that some commission is appointed here also. Let the commission go into these matters and find out whether this community is socially up to the level of the other communities. Let it find out what the position is. If the commission makes a report that this community is socially and educationally a backward community, it is the duty of the Government to lift this community to level of the other communities. I hope the Government will pay special attention to this matter.

Another matter to which I would like to draw the attention of the Government is in regard to the Mopla Rebellion of 1921. Sir, freedom fighters and victims of the freedom movement are being given pensions or other remuneration. But as far as the Mopla Rebellion is concerned, a statement has been made by Mr. Mohsin, the Deputy Home Minister, that the Government does not consider them as freedom fighters. Sir, everybody knows that the Mopla Rebellion of 1921 was a movement started by the Moplas of Malabar at the call of Mahatma Gandhi and Ali Brothers when they called the Khilafat movement; it was nothing but the off-spring of the Khilafat movement. You would find that thousands and thousands of victims are there; their children are there. No pension is being given to them. I appeal to the Government to reconsider their stand and see that the victims of the Mopla Rebellion are also given pensions as freedom fighters.

The other thing is about my own State, Kerala. Everybody knows that Kerala exports coffee, rubber, cashew, etc. and earns foreign exchange for the country as a whole. But at the same time, the financial assistance given to Kerala is quite insufficient for the various development

works. Land reforms have been implemented in letter and spirit. You do not find in Kerala a single landlord. Landlordism has been abolished once and for all. Land has been distributed and permanent ownership is being given to the tenants. But at the same time, financial implications are there in the implementation of land reforms. It is for this that more financial assistance from the Central Government to Kerala is required. With these words, I thank you.

श्री गोलाप बरबोरा (आसाम) उपसभाध्यक्ष जी, श्री चव्हाण साहब जब अपना बजट पेश किये थे तो अपने भाषण मे उन का कहना था कि इस बजट का मार्केट पर कोई बुरा असर नही पडेगा और कोई असर होने से भी बहुत मार्जिनल असर रहेगा और चीजो के दामो को बढने से रोकने का प्रबन्ध किया गया है। लेकिन बजट को पेश किये हुये अभी कुल दो महीने ही गुजरे है और बाजार मे चीजो का दाम काफी बढ गया है, चीजे काफी महगी हो गई है। जहा तक मुझे मालूम है चव्हाण साहब जिस प्रान्त से आते है, वहा आज पाच रुपये किलो गेहू का दाम है, और दस रुपये किलो चावल का दाम है और तमाम महाराष्ट्र के लोग जिन चव्हाण साहब को शिवाजी मानते थे आज वहा उन का घेराव हो रहा है। यह समाजवाद का नक्शा है। अभी अभी कमलनाथ जी का भाषण मै सुन रहा था। बरसो तक मै उन के साथ रहा। बिहार और आसाम का कोना-कोना उन के साथ घूमा हू। वह कह रहे थे कि गरीबी हटाना कोई एक दिन का काम नही है। उसके लिये यू हैव टु टाइटेन दि बेल्ट्स। उस के लिये सेक्रीफाइस करना होगा। जो कुछ आप ने कहा वह ठीक है। प्रधान मन्त्री जी ने गरीबी हटाओ का नारा लगाया है, लेकिन बाद मे बिल्टस के साथ एक इटरव्यू मे उन्होने कहा और एक आम सभा मे और फिर काग्रेसियो की सभा मे भी उन्होने कहा कि गरीबी हटाना किसी एक प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर मे सभव नही है। यह बात मैं भी मानता हू किसी भी अडर डेवलप्ड कट्री मे एक दिन मे उस की आर्थिक हालत को सुधारना सभव नही है। उसके लिय मेहनत करनी पडेगी, उसके लिये काम करना पडेगा और रिसोर्सेज को टैप करना होगा, लेकिन हम देखते है कि उस रास्ते मे भी हम एक कदम नही बढा रहे है। हमारे देश मे फिजूल खर्ची इतनी ज्यादा है कि जिस के कारण एक नया क्लास बन रहा है। बरसो पहले यूगोस्लाविया मे मार्शल टीटो के बाद नम्बर दो के एक नेता ने मिलोभान जीलास जिस को बाद मे जेल मे रखा गया, उन्होने कहा था कि वहा का जो सोशलिज्म है उसमे एक नया क्लास पैदा हो गया है, जिसके पास सारी सहूलियते और सुविधाये है और आज हिन्दुस्तान मे भी समाजवाद के नाम पर ऐसा ही कुछ चल रहा है। कुछ दिन पहले पब्लिक एकाउन्टस कमेटी के साथ मै बम्बई गया था। वहा ओवरसीज कम्युनिकेशन बिल्डिग हम को देखने को मिली। चूकि उस की रिपोर्ट मेरे सामने आई इसलिये उस बारे मे मे बोलना चाहता हू। उस ओवरसीज कम्युनिकेशन बिल्डिग का ठेका डेढ करोड रुपये का था। उस ठेके को देने मे भी काफी घोटाला रहा वह भी पब्लिक एकाउन्टस कमेटी की रिपोर्ट मे है, लेकिन उस डेढ करोड की बिल्डिग मे 35 लाख रुपये का सिर्फ मार्बल लगा। वैसे ही दिल्ली मे हाई कोर्ट की बिल्डिग बनने वाली है उसमे भी दस लाख रुपये का मार्बल लगेगा। हमारे पार्लियामेट हाउस के बाथ रूम्स मे भी मार्बल लग रहे है। तो एक बैकवर्ड कट्री मे क्या जरूरत पडती है जगह-जगह मार्बल लगाने की? बम्बई की ओवरसीज कम्युनिकेशन बिल्डिग मे, डेढ करोड की बिल्डिग मे 35 लाख रुपये का मार्बल लगे जो कि राजस्थान मे 11 रुपये क्युबिक फिट मिलता है और उसके लिये वह बिल 40, 42 रुपय क्युबिक फिट का दिया गया। तो यह जो तरीका है कि ऊपर के कुछ लोग आराम और आशाइस की जिन्दगी बिताये और गरीब और मध्यम श्रेणी के वर्ग के लिये कहा जाय कि वह देश के लिये त्याग करे, बलिदान करे और उन को भूखो मरने का सबक सिखाया जाय यह एक गलत तरीका है। काम करना है तो आइये, हम सब मिल कर करे। हम मानते है कि यह एक बैकवर्ड कट्री है और इस को आग बढ़ाने के लिये

[श्री गोलाप बरबोरा]

त्याग करना है, लेकिन इस मे बडे लोग, न्यु रिच क्लास और अफसर लोग और बिजनेसमैन आराम से जिन्दगी बिताये, उन पर एक रात मे अशोका और ओबराय होटल मे हजारो रुपये खर्च हो और उसी दिल्ली मे एक गरीब आदमी जिसके पास अगर जाडे मे कबल न हो तो वह ठड खाता फिरे, यह कोई रास्ता एक गरीब देश को आगे बढाने का नही है। इसको हमको रोकना चाहिये।

श्रीमन्, रीजनल इम्बैलेम देश मे है और जितना भी हम रीजनल इम्बेलेम को हटाने के बारे मे बोले हम देख रहे है कि आज कुछ इलाके देश मे आगे बढते है और इलाके भी नही बल्कि इलाके के कुछ लोग। इस सदन मे हम देखते है, कि कभी कभी बहस होती है, बगाल वाले महाराष्ट्र को बोलते है कि हमसे इडस्ट्रियल लाइसेस ले गये। इंडस्ट्रियल लाइसेस जो इश्यू हुये उनकी लिस्ट देखते है तो महाराष्ट्र मे ढाई सौ और बगाल मे डेढ सौ लाइसेस और हमारा आसाम जैसे प्रान्त मे सिर्फ 4 लाइसेस। तो बहसबाजी होती है फारवर्ड स्टेट के अन्दर लेकिन और भी स्टेट पडे हुये है जहा कि कोई इडस्ट्रियल लाइसेस मिलता नही है। तो इस तरीके से इस देश को आप आगे नही बढा सकते है। बैकवर्ड जो रीजन्स है उनको बराबरी पर लाने के लिये फाइनेस कमीशन को कुछ ज्यादा एलाटमेट उन स्टेट्स के लिये करना चाहिये और वहा इडस्ट्रीज लगाने की कोशिश होनी चाहिये, लेकिन आज आउट-डेटेड एक तरीका है, कहते है कि वहा कोई इनफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नही है और इसीलिये इडस्ट्रीज नही लगाई जाती। तो इनफ्रास्ट्रक्चर कौन बनायेगा इडस्ट्री लगाने के लिये? इनफ्रास्ट्रक्चर भी आपको तैयार कराना होगा, उसकी जिम्मेदारी भी सरकार की है, उसके लिये भी कुछ सहूलियत करे।

श्रीमन, अनएम्प्लायमेट का सवाल है। देश मे इल्लिट्रेसी का सवाल है। अनएम्प्लायमेट हर पचवर्षीय योजना मे बढता जाता है, पुराने अन-एम्प्लाएड जो लोग है, उनके साथ-साथ और अनएम्प्लाएड जुड जाते है। तो बेकारी की समस्या को हल करने के लिये आपका कोई ठोस कदम नही है। इस देश मे स्कूल, कालेज, युनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी हर दस साल मे इल्लिट्रेट लोगो की सख्या हिन्दुस्तान मे बढती जा रही है, 1961 से 1971 ई० तक की सैसस रिपोर्ट जो है उसके अनुसार निरक्षर लोगो की, इल्लिट्रेट लोगो की, टोटल सख्या करीब 7 करोड बढी है।

उसी तरह भूमि सुधार की बात आप करते है, भूमिहीनो को जमीन देने की बात करते है, लेकिन 1961 से 1971 ई० तक से सैसस के अनुसार दस साल मे भूमिहीनो की तादाद, पापुलेशन 16 परसेट से 22 परसेट तक बढ गई है। इस ढग से आप एनालाइज कर के देखिये तो देश मे गरीब ज्यादा गरीब होते जा रहे है, ज्यादा किसान भूमिहीन होते जा रहे हैं, ज्यादा लोग अनपढ होते जा रहे हैं, और साथ ही साथ समाज का सब कुछ साधन, पूजी, जा कर के कुछ लोगो के हाथ मे जमा हुई है और वह भी ब्लैक मनी के रूप मे और उस ब्लैक मनी का इस्तेमाल करते है फिजूलखर्ची मे देश के रिसोर्सिज को बढाने मे उनको कोई मदद नही मिलती है।

श्रीमन्, जहा रीजनल इम्बैलेम की बात हम कहते है तो उसी के साथ जुडी हुई है एक और समस्या और वह समस्या है ईस्टर्न रीजन की जो जूट और टी इडस्ट्री है उसकी। आसाम जैसे प्रान्त मे 11 लाख बेल्स जूट पैदा होता है और वहा सिर्फ एक जूट मिल है जिसमे 1 लाख बेल्स की खपत है, वहा कम से कम तीन और जूट मिल हो सकती है। वैसे ही चाय का जो उद्योग है हिन्दुस्तान मे उसकी 50 फीसदी चाय आसाम मे पैदा होती है, लेकिन वहा चाय इडस्ट्री की हालत भी बहुत खराब है। अभी-अभी एस्टीमेट्स कमेटी की 28वी रिपोर्ट मे टी इडस्ट्री के बारे मे कुछ सजेशस दिये गये है। टी इडस्ट्री का काफी दिनो से डिमाड रही है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटाये और एक्सपोर्ट ड्यूटी फर्स्ट मार्च, 1970 ई० से हटाई और रिबेट दिया गया एक्सपोर्ट पर 15 अप्रैल, 1970 ई० से। लेकिन जहा 50 पैसे की एक्सपोर्ट ड्यूटी

थी वहा एक्साइज ड्यूटी का एक नया ऐक्ट लागू किया गया—20 पैसे से लेकर एक्सपोर्ट ड्यूटी वहा है करीब 1 रु० 50 पैसे तक। 5 जोन्स बनाये है जिसमे कई एक जोन्स मे 1 रु० 50 पैसे तक एक्साइस ड्यूटी है। एक्सपोर्ट ड्यूटी माफ करके जो कुछ भी राहत टी इन्डस्ट्री को दी गई उससे ज्यादा टैक्स उनसे वसूल किया गया, एक्साइज ड्यूटी का बढा कर। इसके ऊपर ध्यान देना चाहिये। इसकी सारे हिन्दुस्तान की इन्डस्ट्री की हालत बहुत खराब है, दुनिया की मार्केट मे भी जहा तक एक्सपोर्ट का सवाल है—एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट मे है—सीलोन 212 2 मिलियन किलो० मे से 208 3 मिलियन किलोग्राम्स एक्सपोर्ट कर रहा है। और हिन्दुस्तान का 1970 का फिगर भी है कि वह 421 28 मिलियन किलोग्राम्स चाय पैदा करके 208 4 मिलियन किलोग्राम्स एक्सपोर्ट कर रहा है। इस सबके बारे मे सरकार का कहना है कि टी बोर्ड है और एक सब-कमेटी है उसके जरिये देखभाल कर रही है। लेकिन जहा तक सवाल है चाय उद्योग को बचाने के लिये कुछ हो नही रहा है। चाय उद्योग की जनरल प्राफिटेबिलिटी का भी सवाल है। इसकी प्राफिटेबिलिटी, 1965–66 मे जहा 4 3 परसेन्ट रही वह बढ कर 1967–68 मे 6 5 परसेन्ट हुई लेकिन 1968–69 मे फिर 2 1 परसेन्ट मे आ गई। और साथ ही साथ मजदूरो का भी सवाल है चाय उद्योग में। मै असम से आता हू, उस प्रान्त मे 4 लाख लोग चाय बागान के मजदूर आज बेकार है। वैसे ही हिन्दुस्तान के और उद्योगो मे लाखो लोग बेकार हो रहे है।

अभी-अभी पे कमीशन की रिपोर्ट जो कुछ भी अखबारो मे आई है वह पढ कर मजदूर खुश नही है। साथ ही साथ, पे कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेन्ट करने के बारे मे सरकार का क्या रुख है, वह भी अभी तक कहा नही जा रहा है। इसके अलावा, पे कमीशन की रिपोर्ट, जहा तक लोकल बाडीज का सवाल है, पचायत और म्युनिसिपल इम्प्लायीज वगैरह का सवाल है, उन लोगो मे लागू होगी या नही। स्टेट एम्प्लायीज के हित मे सेन्ट्रल पे कमीशन की रिपोर्ट का क्या सम्बन्ध रहेगा, इसके बारे मे भी कहा नही गया साथ ही साथ, रेलवेमैन तथा और भी कर्मचा बोनस और मिनिमम वेजेज के सवाल को लेकर अगले एक महीने मे हडताल मे जाने की धमकी दे रहे है। इसके ऊपर भी सोच विचार होना चाहिये। इस सब परिस्थिति को देखते हुये में यह मानता हू कि देश की आर्थिक अवस्था बहुत खराब है, इस पर सरकार का कोई काबू नही है और इसलिये आज हम देखते है कि प्राइम मिनिस्टर महोदया कोई भी सवाल का इस सदन मे, यहा रहते हुये भी, जवाब नही दे कर पब्लिक मीटिंग्स मे—कही कानपुर मे, कही कोचीन मे, कही बगलौर मे—बोलती है और खास कर अपोजिशन पार्टी पर हमला करती है। काग्रेस के लोगो का यह भी कहना है कि गाव का किसान कही मण्डियो मे गेहू ला कर नही दे रहा है तो वह इसलिये कि ये अपोजिशन के लोग जाकर गलत प्रचार किये है, लोगो मे एक डर पैदा किया है। अपोजिशन तो हिन्दुस्तान मे ऐसा खास है नही। जो कुछ भी है, इस अपोजिशन को आज जाकर बोलने की कोई जरूरत नही है। आज हरियाणा और पजाब की मण्डियो मे लोग अनाज लाने के लिये डर रहे है, घबरा रहे है, क्योकि आप उनसे अनाज लेगे 76 रु० क्विटल और आज बाजार मे 1 रु० 50 पैसे या 1 रु० 60 पैसे किलो के नीचे आटा नही मिल रहा है। यह हालत है। उधर बिजली का दाम बढा, खाद के दाम, पानी के रेट्स ज्यादा हो गये। इतना सब कुछ होते हुये, जो किसान है, उनसे अनाज जो आप लेगे उसके वाजिब दाम क्यो नही देते है। दाम तो आपके तय किये हैं लेकिन किसान के घर मे जो बुनियादी जरूरत की चीजे है उनको किफायती दाम पर देने के लिये क्या व्यवस्था आपने की है? कोई व्यवस्था नही है। इसीलिये किसान घबडा रहे हे और इस बात को लेकर सारे हिन्दुस्तान मे—आपको चेतावनी दे रहा हू एक साधारण नागरिक की हैसियत से—एक बहुत बडा व्यापक असतोष फैल रहा है जो कि और भी ज्यादा फैलने वाला है। और इस चीज को और वहा की जनता की कठिनाई को दूर करने के लिये महाराष्ट्र और गुजरात मे जो कार्यवाही की गई

[श्री गोलाप बरबोरा]

गोली और लाठी का जो इस्तेमाल किया गया, वह बहुत ही शर्मनाक है। आपको देश की परिस्थिति को सुधारना होगा और इस तरह की हालत को गोली और लाठी से सुधारा नही जा सकता है। आपको देश मे बढ़ते हुये दामो को रोकना होगा और अगर आप इस चीज को नही कर पाते हैं तो श्री चव्हाण साहब को इस्तीफा दे देना चाहिये।

कुमारी सरोज पुरुषोत्तम खापर्डे (महाराष्ट्र) माननीय उपसभाध्यक्ष जी, वित्त मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है, उस बजट का मै मन पूर्वक स्वागत करती हू। इस बजट को पेश करते वक्त लोगो को कई अपेक्षा थी, लेकिन उस अपेक्षा के मुताबिक बजट पेश नही हुआ, ऐसा लोगो का कहना है। वह ठीक भी है। एक बात आपने अवश्य की और वह यह है कि आपने गरीबो पर टैक्स नही लगाया। आपने गरीबो पर भले ही टैक्स न लगाया हो, लेकिन गरीबो को इस बजट से किसी प्रकार की राहत नही मिली है। इतना तो मै अवश्य कहूगी कि अगर उन्हें राहत मिली होती, तो शायद आज हम बढती हुई कीमतो का न देखते और इस बढती हुई कीमतो मे आज उन लोगो की चीजो को खरीदने की समर्थता नही रह गई है।

दूसरी बात मै महाराष्ट्र के सम्बन्ध मे कहना चाहती हू। महाराष्ट्र के कुछ इलाको मे जिस तरह की परिस्थितियो का निर्माण हुआ, उसके सम्बन्ध मे मै कुछ उदाहरण देना चाहती हू। मै आपसे कहना चाहती हू कि नागपुर, शोलापुर, मालेगाव तथा अन्य जगहो पर जो परिस्थिति का निर्माण वहा पर पिछले कुछ दिनो मे हुआ वह बहुत ही खेदजनक है। पहला कारण तो इस परिस्थिति के निर्माण होने का खाद्यान रहा, लेकिन साथ ही साथ एक और भी कारण था जिस कारणवश वहा पर परिस्थिति खराब हुई और वह था काटन यार्न की कमी और इन दो कारणो की वजह से उन इलाका मे परिस्थिति खराब हो गई और जटिल बन गई। मै आपके सामने उदाहरण देना चाहती हू कि पिछले 15 दिनो से नागपुर तथा उसके इर्द-गिर्द गावो मे सूत, अनाज और अन्य दुकानो की भयकर लूटमार हुई। महाराष्ट्र के अन्य भागो मे भी विशेषत: नागपुर, मालेगाव, शोलापुर, नासिक, ओडार आदि गावो मे उसी प्रकार से अनाज आदि दुकानो की लूटमार की गई। यहा तक कि सिन्नर मे कचहरी तक को जलाया गया है। पुलिस ने इस उत्पाद को रोकने के लिये लाठी और गोली का सहारा लिया जिससे कई लाग जख्मी हुये और कई लोगो की जाने गई। सामान्यत, कानूनन नही तोडने वाला महाराष्ट्र का जनसमुदाय इस तरह से कानून तोडने पर विवश हुआ। इसका मूल कारण तथा सूत के व्यापार का सरकारीकरण होने के बाद आवश्यक कदम सरकार को उठाने चाहिये थे और अनाज तथा सूत का वितरण योग्य मात्रा मे तथा योग्य मशीनरी द्वारा वितरण करना चाहिये था, जो सरकार नही कर पाई। अशोक मेहता कमेटी की रिपार्ट के अनुसार हमारे देश से 25 से 30 लाख हैडलूम्स है और करीब दो अढाई लाख लोगो की जीविका इस चीज पर निर्भर करती है। केवल महाराष्ट्र मे एक लाख 85 हजार हैडलूम्स है और 90 लाख लोगो की जीविका इस चीज पर निर्भर करती हैं। इसमे से 85 हजार तो कोआपरेटिव सैक्टर मे है और बाकी सारे कोआपरेटिव सैक्टर के बाहर है। आज तक कोआपरेटिव क्षेत्र के बाहर के हैन्डलूम्स के लिये केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार बिलकुल जिम्मेदार नही थी। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के तिडके-समिति की सिफारिशो को स्वीकार करने के बाद 2 अक्तूबर, 1971 से महाराष्ट्र मे हैन्डलूम, पावरलूम तथा सहकारी वस्त्र निर्माण सचालनालय का निर्माण हुआ और महाराष्ट्र राज्य मे हैन्डलूम कारपोरेशन का 1 अक्तूबर 1971 को निर्माण हुआ। इस सस्था का उद्देश्य था सहकारी क्षेत्र के बाहर वाले हैन्ड-लूम को सरक्षण देना तथा उनके माल की पूरी जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्वीकार करना। लेकिन दुर्भाग्य से तिडके समिति की सिफारिशो को अमल मे नही लाया गया, जिसके कारण बुनकरो की समस्या दिन-व-दिन जटिल होती गई, उदाहरण के लिये डाय हाउस, सार्यासग प्लान्ट, सरकारी कर्मचारियो को हैन्डलूम का कपड़ा खरीदने के लिये एक महीने का एडवान्स देकर खादी के सिवाय सरकारी तथा गैर-सरकारी दफ्तरो मे

हैन्डलूम का कपड़ा इस्तेमाल करना आदि अनेक योजनाओ पर डेढ़ वर्ष के बाद भी अमल नही हो सका। राज्य सरकार के बजट मे जो पैसा बुनकरो की योजनाओ के लिये था, उसे उपयोग मे नही लाने के कारण वह पैसा सरकार को लौटा दिया गया। राज्य शासन के बुनकरो को दिये हुये आश्वासन की पूर्ति न करने के कारण और तिड़के समिति की सिफारिशों को अमल में न लाने के कारण बुनकरो की समस्या काफी बिगड़ गई।

बुनकरों को सूत अधिक भाव से खरीदना पडता है कलर कैमिकल्स के भाव मे तेजी होने के कारण बुनकरो के माल की बिक्री की कीमत नही बढ़ सकी। उनको हैन्डलूम का धधा चलाना मुश्किल हो रहा है। सूत के बारे मे आर्टीफीशियल शार्टेज निर्माण की जा रही है, यह सत्य है। व्यापारियो ने यह परिस्थिति जानबूझ कर निर्माण की हुई है, लेकिन साथ ही साथ इसका कारण यह भी है कि बिजली की कटौती 16 प्रतिशत है। सरकार ने यह बिजली कटौती का रुख सूत गिरणी तथा मिल के सूत विभाग के बारे मे नही अपनाया होता तो बुनकरो के लिए शायद यह समस्या गम्भीर न बनती।

इस वर्ष महाराष्ट्र में तीन लाख (गाठे) बेल्स काटन पैदा हुआ है। ऐसी स्थिति मे सरकार ने सूत के वितरण की व्यवस्था ठीक से नही की, वरना शायद ही यह परिस्थिति निर्माण होती। इस मार्च महीने तक बुनकरो के पास सूत नही पहुच सका। सूत के भाव मे काफी तेजी आ गई है और इस परिस्थिति का लाभ व्यापारियो ने उठाया है। नतीजा यह निकला कि भारी दाम में सूत खरीदना गरीब बुनकरो के बस की बात नही थी और उनके सारे रास्ते बन्द हो गए। सूत नही, इसलिए काम नही, काम नहीं इसलिए बढती हुई मंहगाई मे खाने के लिए अनाज नहीं। इसी कारण बुनकर जनता तग आकर चिढ गई और उन्होंने लूटमार की परिस्थिति नागपुर तथा अन्य जगह निर्माण की।

महाराष्ट्र मे 1 लाख 85 हजार हेन्डलूम्स में से 1 लाख विदर्भ मे है। इसमे से नागपुर शहर मे 27 हजार है। उस पर डेढ़ लाख लोगो की उपजीविका निर्भर है। सूत की परिस्थिति सुधारने के लिए मै अपनी दृष्टि से कुछ सुझाव देना चाहती हू.—

1. राज्य सरकार सूत गिरणी तथा मिलो के सूत विभाग पर लगाया हुआ बिजली कटौती का बधन शिथिल करे।

2 मिल और सूत गिरणी चौबीस घटे उत्पादन करके हैन्डलूम के लिए लगने वाले हैक बेल्स के रूप मे उचे नम्बर का सूत उत्पादन करे।

3. राज्य सरकार को सुयोग्य यत्रणा निर्माण करके बुनकरो को प्रत्यक्ष रूप मे सूत का वितरण करना चाहिए और उसके अमल पर सख्त नजर रखनी चाहिए।

वास्तव मे महाराष्ट्र सरकार को अनाज के व्यापार के सरकारीकरण के बाद अनाज की वसूली जिस तेजी से करना आवश्यक था उस तेजी से वसूली नही कर पाई। आज भी इतना सारा होने के बाद भी राज्य मे किसानो से अनाज की वसूली सतोषजनक नही है। अनाज और सूत के व्यापार को सरकार ने जो अपने हाथ मे लिया है उसको किसी तरह से असफल करने की व्यापारियो ने ठान ली है। इस सारी स्थिति का परिणाम यह हो रहा है कि जनता उत्तेजित होकर दगे-फसाद करने पर मजबूर हो गई है। इतना ही नही विरोधी लोग सीधी-सादी जनता को बहका कर दगा-फिसाद कराने मे और हमारी सरकार को बदनाम करने मे लगे रहते है।

इतना ही नही, मै तो आपको इसके आगे भी जाकर कहना चाहती थी और वह है कि जैसे पिछली एक मई को सारा नागपुर ही नही सारा विदर्भ बन्द का काल दिया गया था उस वक्त हम सब लोगो के मन में एक प्रकार का भाव था कि यह सही माने मे सेपरेट विदर्भ की माग कर रहे है। लेकिन हमने यह देखा है कि सारे लोग इतनी तादाद मे अपनी-अपनी दुकाने बन्द करके भयभीत हो गये थे। उसका कारण यह था कि दुकानदारो ने सैपरेट विदर्भ की डिमाड

[कुमारी सरोज पुरुषोत्तम खापर्डे]

पर अपनी दुकाने बन्द नही रखे हुए थे, बल्कि उसका कारण यह था कि बुनकरो की जटिल समस्या काटन यार्न की थी। दूसरी बात बढ़ती हुई कीमतो से लोग परेशान थे, तीसरी बात यह रही कि अनाज की समस्या किसी स्टेट मे ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नही होगा जहाँ न हो। जहा सूखा पड़ा है वहां निश्चित तौर पर फूड प्राब्लम है। इन्ही तीन कारणो से विदर्भ बन्द रहा। दूसरा, मुझे यह लगता है कि नागपुर महाराष्ट्र का सेकिड कैपिटल है सेकिड कैपिटल होने के बावजूद भी आज विदर्भ के लिए जो कहते है कि हम सैपरेट विदर्भ चाहते हैं, उसका कारण मुझे लगता है कि जैसे बम्बई शहर मे बड़े-बड़े कारखाने है, इडस्ट्रीज है, औद्योगिक कारखाने है, उसे कपेरिजन की दृष्टि से देखने है तो विदर्भ में कोई बड़ी इडस्ट्री नही है। इसलिए मुझे लगता है कि लोगो के दिमाग से अलग विदर्भ की यह माग, यह चीज निकाल दे, अगर हमारी सरकार विदर्भ मे बडी-बडी इंडस्ट्रीज लगाये और विदर्भ का उत्थान कर सके तो लोगो के दिमाग से यह बात निकल जाएगी।

अन्त में मै केन्द्रीय सरकार से कहना चाहती हू कि महाराष्ट्र मे काटन यार्न और फूड सिचुएशन का निर्माण हुआ है। इसकी ओर अधिक ध्यान देकर महाराष्ट्र की जनता को दगे फसादो से बचाने की चेष्टा करे।

मुझे आपने अपने विचार मदन के सामने रखने का जो अवसर दिया है उसके लिए मैं आपकी आभारी हूं।

SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA (Mysore) : Mr. Vice-Chairman, Sir, as usual we are getting time at the tail end of the day and instead of speaking here I can as well go over to the Finance Minister and present my case to him because there is nobody here. .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU) : Mr. Gowda, if you do not want to speak now...

SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA : No, no; I do want. I am only saying this is the situation which I always find myself in every time I rise to speak.

SHRI OM MEHTA : I would request him to join some party and to find himself in a better situation.

SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA : Thank you very much; I will certainly consider that.

Mr. Vice-Chairman, this Rajya Sabha participating in the discussion on the Finance Bill is more or less a formality. We will have made our suggestions during the general discussion on the Budget and now that Mr. Chavan has already got the Finance Bill passed in the Lok Sabha it is only a mere formality and whatever views we may have to express we would express so that at least for the next Finance Bill he could give some consideration to the points which we make now.

In his speech when he introduced the Bill, the avowed object was to promote savings and investment, to enlarge employment opportunities, to ensure minimum basic amenities to all citizens and to give a boost to our exports. With the limited resources available and in the difficult situation in the country I should say that Mr. Chavan has tried to do his best but unfortunately when we find the final outcome of this Bill I do not know to what extent these objectives could be achieved by the Finance Bill which is now being passed.

The first thing I would like to mention here is about a subject in which I myself am concerned and Mr. Chavan was good enough to start off his speech today with that, that is, the aggregation of the agricultural income-tax and general income-tax for the purpose of computing the tax. When the general discussion on the Budget took place, I myself made this very point and requested him to give us some concession or consider giving a rebate for the agricultural income-tax which is paid, in

at least the States in which the agricultural income-tax Act is in force. I am very happy that he has considered and conceded that point and I congratulate him on that and I thank him for that. While doing that I would like to mention here certain difficulties which arise. The agricultural income-tax Act is in existence in the three Southern States, *i.e.*, Mysore, Madras and Kerala, where more than general agriculture, commercial crops like plantation crops give the major yield from agricultural income-tax. I understand that there are agricultural income-tax Acts in Assam, Maharashtra and other places where it covers general agriculture. In Maharashtra the exemption limit is very high, *viz.*, Rs. 36,000 and so the actual incidence of tax is very low. In the Southern States the agricultural income-tax Acts are exactly on the lines of the Central Income-tax Act, which taxes income over Rs. 5,000. Why I am mentioning this here is that the agricultural income-tax which is paid will be given a rebate as provided in clause 8 while calculating the aggregate income now, but there are still certain other difficulties which will arise, like losses which will accrue out of agricultural income, the suggestion has been made that it will be set off only against the agricultural portion of the income. When there is a higher earning by aggregating the two, the tax will be at the higher rate on the non-agriculture portion, but when there is a loss, it is set off only against the agricultural portion of it This will not give the relief which I thought it would provide. Then, another practical difficulty about this is that the Central income-tax assessing authorities will have to wait until the agricultural income-tax assessments are finalised for determining in such States the agricultural income portion of it. I suggest that this matter must be taken up with the State Governments to see that the agricultural income-tax assessments are completed by the time the Central assessments commence. Otherwise, there will be delay and there will be difficulties for the assessees.

Another thing I would like to mention is that in certain States even where agricultural income-tax is in force, agricultural commodities like paddy, wheat and rice are not covered. How are they going to be assessed? Another problem is when you come to States like Haryana where there is no agricultural income-tax. If there are people with non-agricultural income and also agricultural income, how do you propose to assess the agricultural income? Since there is no Act, some method has to be found. I cannot say whether any method has been introduced for that and whether it is going to be done at the stage of the rules. Unless that is done, the entire assessment on the non-agricultural income of persons who have also agricultural income in those States will be held up for a long time. Some method will have to be found for that. No doubt, the relief he has provided is considerable, but I would like to point out here the case of an assessee who has a small non-agricultural income and a large agricultural income. For example, let us take an agriculturist who has husbanded his resources and he has put his money in the banks or in shares or in other investments and mainly out of that he gets about Rs. 20,000 as non-agricultural income. This sum of Rs. 20,000 now attracts a tax of, say, 20 or 23 or 25 per cent at the most. Then, let us say his agricultural income is Rs. 60,000 or Rs. 80,000. When this aggregation comes, the aggregate income will be Rs. 1,00,000 and this sum of Rs. 20,000 will be taxable at the rate applicable to Rs. 1,00,000 minus the agricultural income-tax he has paid, if any. That will immediately put up the rate of tax for the non-agricultural income to 70 or 75 per cent. So, the investment climate that he has provided for the small investor by giving rebate upto Rs. 3000 rebate of income-tax for investment in the bank deposits etc., will be nullified by this taxation going up to 70 to 80 per cent. Out of the Rs. 20,000 he will hardly get Rs. 5,000 and how does the Government expect people to make investments in the nationalised banks or put in shares, etc? This is a hardship which is still there. We can know it only at the working stage. Otherwise, if you take only the case of a person

[Shri U. K. Lakshmana Gowda]

who has only Rs. 15,000 of agricultural income, it does not give this picture at all. This is a point which I would like him to bear in mind and see what relief he can provide by the time this comes into force in 1974.

Going into the details of the Finance Bill about the resources which have been tried to be mobilised, direct and indirect resources, the non-tax resources proposed to be raised are very limited. As for example, I would like to quote here that a commendable effort is being made to make the public sector industries yield a better return, which will form as non-tax resources, and he has enumerated certain measures which have been taken and also the efforts which are being made by the Government. But I am sorry to say that in spite of that, we see that out of the five thousand crores of investment in public sector, even if we get 5 per cent return on that, we should have Rs. 250 crores. But as against this the public sector shows an approximate cumulative loss of Rs. 18 crores now. A very considerable effort has to be made in this direction now and in future; otherwise, this will upset any of the non-tax resources which you would like to generate for the economy.

Then when we come to the question of direct taxes which are not very considerable but look at the taxation structure, India is probably one of the highest individually taxed countries in the world. Even the Wanchoo Committee in its recommendation has felt that unless something is done about marginal taxation at the highest level—which goes up to 97 per cent—there is hardly any saving and any incentive for saving and the savings will be only from the tax-evaders or the smugglers. That is the only saving section. This is a matter which should be looked into. But, unfortunately, when the other recommendations of the Committee are being considered, this has been left out. I hope that some consideration will be given to it so that the tax will be in such a way that sufficient incentive will be available for individual saving.

I would like to point out another thing that is in view of the eroding value of the rupee, this exemption limit which has been put at Rs. 5000 is rather ridiculously low by today's comparison. It should have been raised to Rs. 7500 at least. Hardly the rupee is worth about thirty paise only, and I hope that in the next Budget he would consider raising the exemption limit to Rs. 7500 which will give relief to the salaried people and also the smaller income group and it will also save the expenditure in covering this vast number of assessees whose exemption limit is just Rs. 5000.

With regard to the savings, with the ever-increasing price-line with respect to consumer goods and also essential commodities, where is the scope for saving? Money circulation in comparison to the rate of growth has increased too high. Actually, it is an accepted fact that money supply should not be more than two to three per cent of the rate of growth. If we look at the picture we find that when the rate of growth has been hardly 1.5 per cent, the money supply has increased from two to three per cent. How does it allow for any citizen to make any saving? So, this becomes only a matter put on paper but in actual practice you could not have any saving, and the savings will be only of the tax-evaders and others. Another thing is, Mr. Chavan...

6 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU) : You have made your points.

SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA : Sir, give me a few minutes. It is the tail end and you can give me another five or ten minutes. Or I am prepared to continue tomorrow.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU) : You take five minutes more and conclude.

SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA : Sir, I am speaking only on the Finance

Bill. I have not gone to the entire gamut of the political situation in the country...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU) : You have made your major points.

SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA : . .and you cut me out within ten minutes.

SHRI S. S. MARISWAMY : He can continue tomorrow.

SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA : Yes, I will take ten minutes tomorrow and finish. That is better.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU) : You can take five minutes now and complete.

SHRI S. S. MARISWAMY : Let him continue tomorrow.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): All right The House stands adjourned till 11 A M. tomorrow.

The House then adjourned at one minute past six of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 8th May, 1973.

MGIPRRND—16RSS/73—Sec. II (Night)—18-7-73—570.